UNIT - V

Investment Criteria in Economic Development

2019 आर्थिक विकास में निवेश मापदण्ड को समझाइए। (5M)

आर्थिक विकास में निवेश कसौटियाँ

2020 निवेश के विभिन्न मापदण्ड सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए (5M)

अल्पविकसित देशों में निवेश कसौटियों की आवश्यकता

(Need for investment criteria in LDCs)

<u>आशय</u> :- निवेश कसौटियों से अभिप्राय उन दिशा निर्देशों से है जिनके अनुसार एक अल्पविकसित देश में आयोजन प्राधिकरण द्वारा निवेश का आवंटन योजना के उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों और परियोजनाओं में किया जाता है।

प्रत्येक अल्पविकसित देश में उत्पादकीय संसाधन दुर्लभ होते हैं तथा उनका आवंटन एक जटिल समस्या है, क्योंकि कोई भी देश अपने संसाधनों का अनियमित ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है। संसाधनों के उचित उपयोग पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है तथा संसाधनों के उपयोग, निवेश नीतियों पर निर्भर करते हैं। अतः आर्थिक विकास निवेश के आवंटन से जुड़ा हुआ है।

निवेश कसौटियाँ

(Investment Criteria)

↓

① पूँजी आवर्त कसौटी
② सामाजिक सीमान्त उत्पादिता की कसौटी
③ पुनर्निवेश कसौटी
④ सेन की काल श्रेणी कसौटी

2013 (5M) → पूँजी आवर्त मापदण्ड को समझाइए।
2018 (5M)

(1) पूँजी आवर्त कसौटी (The Capital Turnover Criterion):-

पूँजी-आवर्त कसौटी कई नामों से प्रसिद्ध है, जैसे आवर्त की दर की कसौटी अथवा पूँजी की प्रति इकाई उत्पादन को अधिकतम बनाने की कसौटी अथवा उत्पादन से पूँजी अनुपात की कसौटी (न्यूनतम पूँजी गहनता अथवा न्यूनतम पूँजी-उत्पादन अनुपात कसौटी) यह कसौटी प्रो० जे०जी० पोलक तथा प्रो० एन० एस० बुकैनन के नामों से सम्बन्धित है। अल्पविकसित देशों में पूँजी दुर्लभ होती है, इसलिए ऐसी तकनीकें चुनी जाएँ जो नियुक्त पूँजी की प्रति इकाई पर अधिकतम उत्पादन प्रदान करें।

सीमाएँ

1. यह समय के तत्व को छोड़ देता है। हो सकता है कि जिन शीघ्र फलदायक परियोजनाओं का पूँजी-उत्पादन अनुपात अल्पकालीन में कम हो, उनका यह अनुपात दीर्घकालीन में ऊँचा हो जाए।

2. यह कसौटी निवेश परियोजना से प्राप्त होने वाले पूरक लाभों की उपेक्षा करती है।

3. कृषि जैसे कुछ उद्योगों में बाहरी तौर से कम पूँजी-उत्पादन अनुपात प्रतीत हो। यदि स्थिर पूँजी निवेश में खाद इत्यादि की कार्यकारी पूँजी को भी शामिल कर दी जाए, तो हो सकता है कि अनुपात वास्तव में अधिक हो जाए।

4. आवर्त की दर जितनी ऊँची होगी, पूँजी के मूल्यह्रास की दर भी इतनी ही अधिक होगी और हो सकता है कि उत्पादन की दर अधिक न हो।

2013 → सीमांत सामाजिक उत्पादकता सिद्धान्त को बताइए। (2M), 2018 (2M)

(5) इस कसौटी में निहित, रोजगार को अधिकतम बनाने का तर्क केवल अल्पकालीन में सही ठहरता है।

(6) यह आवश्यक नहीं कि रोजगार बढ़ने पर कुल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। श्रम गहनता तथा पूँजी बचतकारी निवेश, कुल उत्पादन में बिल्कुल वृद्धि किए बिना, श्रम की उत्पादकता को यथावत कम रख सकते हैं।

<u>निष्कर्ष</u>:- इस प्रकार, पूँजी आवर्त कसौटी अनेक साधनों से घिरी रहती है। इसमें सन्देह नहीं कि सामान्य संबोध यह माँग करता है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रचुर श्रम तथा दुर्लभ पूँजी को देखते हुए कम पूँजी-गहनता की परियोजनाएँ शुरु करनी चाहिए, परन्तु यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि ~~सामाजि~~ सामाजार्थिक आधारित संरचना का निर्माण करने के लिए और आर्थिक विकास की दर बढ़ाने के लिए, अधिक पूँजी गहनता वाली परियोजनाएँ भी नितान्त अनिवार्य हैं। भारत अपने आर्थिक विकास की परियोजनाओं में दूरदर्शिता से इस दोहरी निवेश नीति का अनुसरण कर रहा है।

(2) सामाजिक सीमान्त उत्पादिता की कसौटी

(The Social Marginal Productivity Criterion)

सामाजिक सीमान्त उत्पादिता (SMP) कसौटी पहले पहल <u>प्रो॰ ए॰ ई॰ काहन</u> ने प्रस्तुत की और बाद में <u>होलिस बी॰ चेनरी</u> ने उसमें सुधार किया। यह परम्परागत सीमान्त उत्पादिता सिद्धान्त पर आधारित है। जब किसी परियोजना में, अन्य आगतों की दी हुई मात्राओं के साथ और अधिक पूँजी लगाई जाती है, तो एक समय के बाद उसका सीमान्त उत्पादन तब तक गिरता चलेगा, जब तक विभिन्न

प्रयोगों में पूँजी की सीमान्त उत्पादिता समान नहीं हो जाती। सीमित निवेश साधनों को ऐसे ढंग से वितरित किया जाए कि राष्ट्रीय उत्पादन अधिकतम बनाया जा सके।

भुगतान-शेष को संतुलन में मानकर चेनरी का बनाया हुआ समीकरण यह है:

$$SMP = \frac{X+E-L-M-O}{K}$$

X = उत्पादन के बढ़े हुए मार्केट मूल्य

E = उत्पादन में जोड़े हुए मूल्य

L = श्रम की लागत

M = माल की लागत

O = उपरि लागतों की जिनमें मूल्यह्रास भी शामिल है।

K = निवेशित पूँजी निधि

$\frac{V-C}{K}$ जो घरेलू रूप से जोड़ा हुआ सामाजिक मूल्य V बराबर है। [X+E] और साधनों की कुल लागत C बराबर है।

$$SMP = \frac{V-C}{K} + \frac{r(\alpha B_1 + B_2)}{K}$$

$$SMP = \frac{V-C}{K} + \frac{Br}{K}$$

प्रो० चेनरी ने इटली तथा यूनान की अनेक निवेश परियोजनाओं की SMP का हिसाब लगाया है।

सीमाएँ (Limitation) -

(1) यह कहना ठीक नहीं है कि पूँजी की सीमान्त उत्पादिता सब प्रयोगों में एकदम बराबर होती है। अधिक से अधिक यह लगभग समान हो सकती है क्योंकि तकनीकी कारणों से निवेश या तो बहुत अधिक होते हैं, या फिर बहुत कम।

(2) विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति में पूँजी की सीमान्त उत्पादिता विशिष्ट प्रौद्योगिकी के आधार पर समान बनती है, जोकि सम्भव है, निवेशित निधियों के पुनर्वितरण की आवश्यक न बनाए।

(3) SMP कसौटी केवल वर्तमान के प्रभावों पर विचार करती है।

(4) SMP कसौटी अस्पष्ट तथा अनिश्चित है क्योंकि वर्तमान तथा भविष्य दोनों में ही विभिन्न परियोजनाओं के लाभों तथा लागत को ठीक-ठीक निर्धारित करना कठिन है।

(5) निष्क्रिय साधन भी होते हैं, जैसे कि अल्प रोजगार तथा बेरोजगार जन-शक्ति, जिनका मार्केट-मूल्य नहीं आँका जा सकता।

(6) SMP कसौटी का एक बड़ा दोष यह है कि यह निवेश के राष्ट्रीय आय पर एकबारगी निश्चित प्रभाव से सम्बन्ध रखती है और भावी आय पर वर्तमान निवेश के गुणक प्रभाव की उपेक्षा कर देती है।

2013 (2M) → पुनर्निवेश मापदण्ड क्या है?

(3) पुनर्निवेश कसौटी (The Reinvestment Criterion)

पुनर्निवेश कसौटी प्रो॰ गलेन्सन तथा प्रो॰ लीबन्स्टीन ने प्रस्तुत की है। इसे अतिरेक की दर सिद्धान्त अथवा सीमान्त प्रति व्यक्ति निवेश गुणांक भी कहा जाता है। उपरोक्त को प्रति श्रमिक शुद्ध उत्पादकता घटा प्रति श्रमिक उपभोग के रूप में परिभाषित किया गया है। गलेन्सन तथा लीबन्स्टीन वर्तमान की बजाय भविष्य में प्रति व्यक्ति उत्पादन को अधिकतम करने पर बल देते हैं।

राष्ट्रीय आय, मजदूरी तथा लाभों में विभक्त है; मजदूरी तो उपभोग पर खर्च हो जाती है और लाभ निवेश के उद्देश्य से बचा लिए जाते हैं। लाभों का परिमाण जितना अधिक होगा, बचतों की दर भी उतनी ऊँची होगी परिणामतः प्रति व्यक्ति पूँजी की उपलब्ध मात्रा भी उतनी ही बड़ी होगी और उत्पादन की वृद्धि दर भी उतनी ही अधिक होगी जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ेगा।

निवेश अतिरेक (r) की दर निर्धारित करने के लिए गलेन्सन तथा लीबन्स्टीन निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं:

$$r = \frac{p - e.w}{c}$$

p = प्रति मशीन उत्पादन है

e = प्रति मशीन मनुष्यों की संख्या

w = वास्तविक मजदूरी दर

c = मशीन की लागत

c के अनुपात में p को बढ़ा कर और e.w को घटा कर अतिरेक r बढ़ाया जा सकता है।

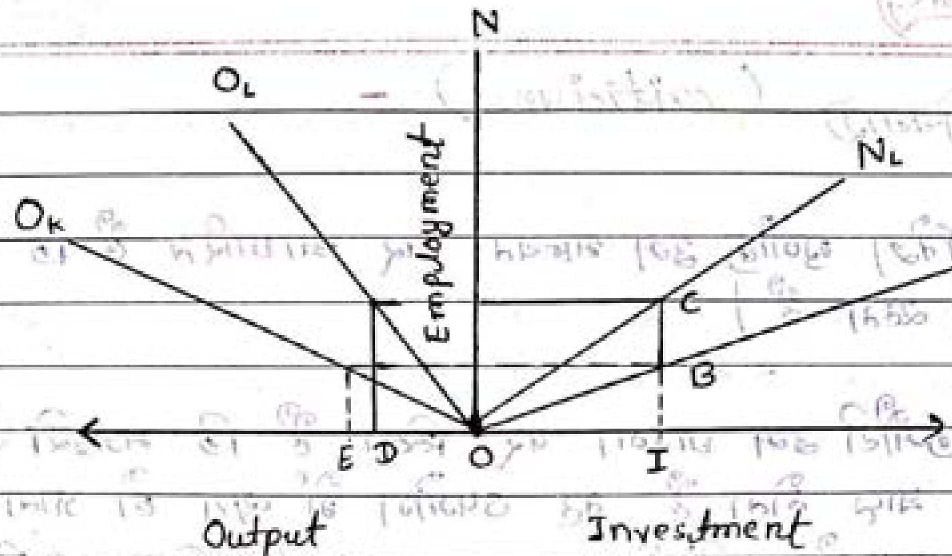

अधिक लाभ होने पर बचतें भी अधिक होंगी। परिणामस्वरूप, निवेश के लिए अधिक पूँजी उपलब्ध होगी तथा उत्पादन में अधिक वृद्धि। उत्तर-पूर्व चतुर्थांश में नए निवेश और उससे होने वाले N रोजगार में परिवर्तनों के सम्बन्ध को व्यक्त किया गया है। N_K किरण इस सम्बन्ध को दर्शाती है जब एक पूँजी प्रधान तकनीक प्रयोग की जाती है तथा N_L किरण जब एक श्रम प्रधान तकनीक प्रयोग की जाती है। उत्तर पश्चिम चतुर्थांश रोजगार और उत्पादन में सम्बन्ध को व्यक्त करता है। O_K = पूँजी प्रधान तकनीक

O_L = श्रम प्रधान तकनीक

नया निवेश OI होता है, पूँजी प्रधान तकनीक IB रोजगार पैदा करती है जब कि श्रम प्रधान तकनीक IC रोजगार उत्पन्न करती है। परन्तु श्रम प्रधान तकनीक केवल OD उत्पादन का निर्माण करती है जबकि पूँजी प्रधान तकनीक अधिक उत्पादन OE का निर्माण करती है। इस प्रकार, पूँजी प्रधान तकनीक कम रोजगार पूँजी गहन उद्योगों की स्थापना के माध्यम परन्तु अधिक उत्पादन निर्मित करती है जबकि श्रम प्रधान तकनीक अधिक रोजगार और कम उत्पादन।

आलोचनाएँ (criticisms) -

① पुनर्निवेश गुणांक इस मान्यता पर आधारित है कि समयोपरि उपभोग स्थिर रहता है।

② यह कसौटी इस धारणा पर स्थित है कि मजदूरी के रूप में जो कुछ प्राप्त होता है वह उपभोग में व्यय हो जाता है, और जो कुछ श्रम को नहीं दिया जाता, वह पुनर्निवेशित कर दिया जाता है।

③ इस कसौटी में पूँजी के मूल्यह्रास के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं रखी गई, जो पुनर्निवेशित अतिरेक को निश्चित ही कम करेगा।

④ यह कसौटी पूँजी की सीमान्त उत्पादिता के नियम के विरुद्ध पड़ती है।

⑤ यह सकथन ठीक नहीं प्रतीत होता कि अत्यन्त पूँजी गहन प्रक्रियाओं में बड़ा पुनर्निवेशन सम्भाव्य रहता है।

⑥ अल्पविकसित देशों में, बड़े पैमाने के पूँजी गहन उद्योगों पर संकेन्द्रण अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों से घिरा रहता है।

⑦ पुनर्निवेशित कसौटी एकांगी है क्योंकि वह भुगतान - शेष के निवेश पर प्रभाव का अध्ययन नहीं करती।

निष्कर्ष :- इन परिसीमाओं के बावजूद, पुनर्निवेश कसौटी अल्पविकसित देशों की आय वृद्धि दर के त्वरण के लिए प्रथम सन्निकटन के रूप में उपयोगी है। सामाजिक सीमान्त उत्पादित कसौटी की अपेक्षा यह कसौटी अधिक यथार्थिक है, क्योंकि यह निवेश की दर पर जनसंख्या वृद्धि के भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करती है।

(4) सेन की काल श्रेणी कसौटी (Sen's Time Series Criterion)

सेन ने "काल श्रेणी" कसौटी प्रस्तुत की है। यह कसौटी काल की दी हुई निश्चित अवधि के भीतर उत्पादन को अधिकतम बनाने का प्रयत्न करती है। पूँजी उत्पादन अनुपात तथा बचत की दर के दिए हुए होने पर (मान लो)

दो तकनीकों (पूँजी - गहन तथा श्रम गहन) का काल - मार्ग खींचा जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है कि दोनों में से कौन - सी तकनीक काल - क्षितिज पर अधिकतम प्रतिफल प्रदान करेगी। मान लीजिए कि दो परियोजनाएँ H (पूँजी गहन) तथा L (श्रम गहन) हैं, और काल क्षितिज दस वर्ष है, जिसके अन्त में, प्रत्येक अवस्था में कुल प्रतिफल 100 मिलियन (10 करोड़) है।

तालिका

अवधि (वर्षों में)	परियोजना 1 (पूँजी गहन) (H) (प्रतिफल मिलियनों में)	परियोजना II (श्रम - गहन) (L) (प्रतिफल मिलियनों में)
1	4.0	6.0
2	5.0	7.0
3	6.0	8.0
4	7.5	9.0
5	9.0	10.0
6	10.5	11.0
7	12.00	11.5
8	13.5	12.0
9	15.00	12.5
10	17.5	13.0
	100.0	100.0

(a) — परियोजना H के वर्ष 7–10 के लिए; (b) — परियोजना L के वर्ष 1–6 के लिए

पहले छः वर्षों में परियोजना L के प्रतिफलों (51 मिलियन) की तुलना में परियोजना H के प्रतिफल (42 मिलियन) हैं, जबकि बाकी चार वर्षों में परियोजना H के प्रतिफल परियोजना L के प्रतिफलों से बढ़ जाते हैं। परियोजना H में प्रतिफल 42 मिलियन से बढ़कर 58 मिलियन हो जाते हैं और परियोजना L में 51 मिलियन से घटकर (49) मिलियन रह जाते हैं, क्योंकि दोनों परियोजनाओं से प्रतिफल समान (अर्थात 100 मिलियन) हैं, इसलिए कुल मिलाकर उदासीनता की स्थिति रहती है।

(a) L की अपेक्षा अतिरेक 58.0 − 49.0 = 9.0
(b) H की अपेक्षा अतिरेक 51.0 − 42.0 = 9.0

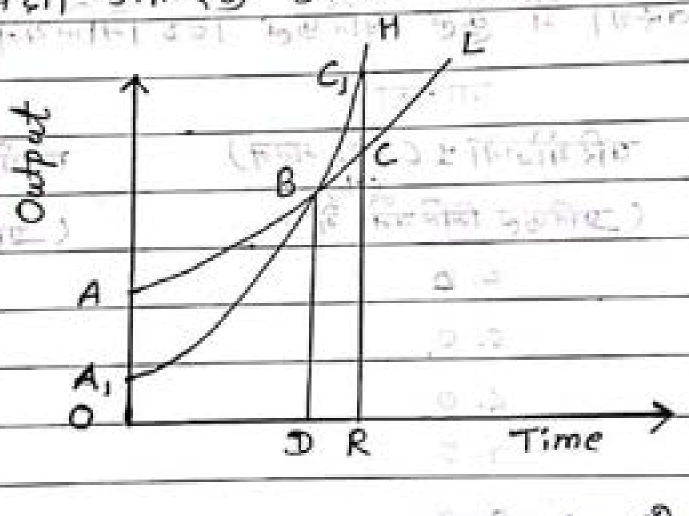

H तथा L वक्र, दिए हुए काल क्षितिज के दौरान दोनों तकनीकों से वास्तविक उत्पादन के प्रवाह को प्रकट करते हैं। तकनीक H शुरू में तकनीक L की अपेक्षा कम उत्पादन किन्तु वृद्धि की अधिक ऊँची दर देती है। समय की D अवधि तक H तकनीक की अपेक्षा L तकनीक अधिक उत्पादन देती है। समय के R बिन्दु पर H तकनीक उस कमी को पूरा कर लेती है जबकि वह तकनीक L की अपेक्षा CBC_1 अधिक उत्पादन देती है। अवधि OR पुनः प्राप्ति की अवधि है जो ABA_1 क्षेत्र = CBC_1 क्षेत्र बनाती है।

इसके लिए निम्नलिखित निर्णय नियम हैं:
(क) जब R > C, तकनीक L चुननी चाहिए।
(ख) जब R < C, तकनीक M चुननी चाहिए।
(ग) जब R = C दोनों में से कोई भी चुनी जा सकती है।

सीमाएँ (limitation) -

① एक विशिष्ट काल-क्षितिज, मान लीजिए दस वर्ष, लेना मनमाना है।

② काल श्रेणी को हमेशा के लिए चलाना सम्भव नहीं है इसलिए निवेश-अवधि निश्चित रूप से नियत करनी पड़ती है।

③ वे साधन-जैसे प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, मजदूरी-दर, उपभोग प्रवृत्ति इत्यादि, जिन पर काल श्रेणी का अध्ययन निर्भर करता है - सभी परिवर्तित हो रहे हो और भावी निवेश तथा उत्पादन सम्बन्धी पूर्वकथन को केवल कठिन ही नहीं बल्कि गलत भी बना दें।

④ इस सिद्धान्त में कुछ भी नई बात नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion):- जिन विविध निवेश कसौटियों की ऊपर चर्चा की गई है, वे अपने अन्तिम लक्ष्य राष्ट्रीय उत्पादन को अधिकतम बनाने की दृष्टि से भिन्न-भिन्न नहीं हैं; कुल राष्ट्रीय उत्पादन को अधिकतम बनाने के लिए, अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवयवों (उपभोग, बचत तथा निवेश) में से एक या दूसरे को न्यूनाधिक महत्व देकर उनका प्रयोग करते हैं। कुछ निवेश कसौटियों का लक्ष्य एक निश्चित समय पर, जबकि दूसरों का

2017 → तकनीक के चयन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए।
2013 → तकनीक के चयन से आप क्या समझते हैं? (3 M)

एक समयावधि में कुल उत्पादन को अधिकतम बनाना है परन्तु सभी कसौटियाँ अधूरी हैं क्योंकि वे किसी न किसी रूप में, निम्न स्तर पर पड़ने वाले कैसे साधनों के प्रभाव की अपेक्षा करती हैं जैसे कि जनसंख्या, वृद्धि, रुचियों, तकनीकी प्रगति, मार्केट स्थितियाँ, आय का वितरण, कीमत-परिवर्तन, भुगतान-शेष और सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियाँ। विपरीतत: वे इन साधनों पर निवेश के प्रभाव का अध्ययन करने में असमर्थ रहते हैं।

The Choice of Techniques

तकनीकों का चुनाव

तकनीकों के चुनाव की समस्या

The Problem of Choice of Techniques

<u>अर्थ</u>:- तकनीकों के चुनाव की समस्या किसी विशिष्ट परियोजना अथवा उद्यम के लिए संयोगों के प्रकार को निर्दिष्ट करती है। किसी विशिष्ट स्थिति में चुना गया संयोग तकनीक के रूप को बताता है। अल्पविकसित देश के लिए श्रम तथा पूँजी-तकनीकों के बीच हल्के तथा भारी उद्योगों के बीच, और कृषि तथा उद्योग के बीच विकल्प विद्यमान रहते हैं। परन्तु अन्तिम चुनाव श्रम-गहन तथा पूँजी-गहन विधियों में से चुनने का रहता है, चाहे वह कृषि और उद्योग में हो अथवा हल्के तथा भारी उद्योगों में हो।

प्रौद्योगिकीय विकास की प्रक्रिया
(Process of technological development) -

प्रौद्योगिकीय विकास के लिए समाज को एक लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है - साधारण से जटिल तकनीकों पर, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तकनीकों से दूर स्थित मार्केटों के लिए तकनीकों पर और देशीय साधनों का उपयोग करने वाली तकनीकों से विदेशी पूँजी की आवश्यकता रखने वाली तकनीकों पर आना पड़ता है।

प्रो॰ कुजनेट्स ने प्रौद्योगिकी की वृद्धि में कुछ विशिष्ट आदर्श अनुरेखित किए हैं:

1. वैज्ञानिक खोज अथवा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि
2. आविष्कार, अर्थात पहले से वर्तमान ज्ञान का उपयोगी साध्य के लिए उपयोग करना
3. नवप्रवर्तन जिसका मतलब है आर्थिक उत्पादन के लिए आविष्कार का महत्वपूर्ण व्यवहार
4. सुधार, जोकि आविष्कार में छोटे लाभदायक परिवर्तन को प्रकट करता है
5. सामान्य रूप से सुधारों के साथ नवप्रवर्तन का प्रसार।

प्रौद्योगिकी के विकास में इन क्रमिक अवस्थाओं की सफलतापूर्ण पूर्ति के लिए स्तर साधनों की आवश्यकता होती है:-

1. संवर्धित वैज्ञानिक ज्ञान का होना एक आवश्यक शर्त है।
2. प्रत्येक अवस्था के लिए भारी पूँजी-निवेश तथा कुशल श्रम-शक्ति की जरूरत होती है।

③ ~~नवप्रवर्तनों~~ नवप्रवर्तनों के लिए उद्यमीय कुशलता तथा योग्यता आवश्यक है ताकि आविष्कारों को लाभदायक उपयोगों में लगाया जा सके।

अन्तिम → नवप्रवर्तनों का प्रसार इस बात पर निर्भर रहता है कि लोग आधुनिक उत्पादन के लिए नई वस्तुओं तथा प्रक्रियाओं को अपनाने को तैयार हैं या नहीं। इस प्रकार, प्रौद्योगिकीय विकास का होना आर्थिक वृद्धि के लिए एक आवश्यक शर्त है।

श्रम गहन तकनीक
(Labour intensive techniques) –

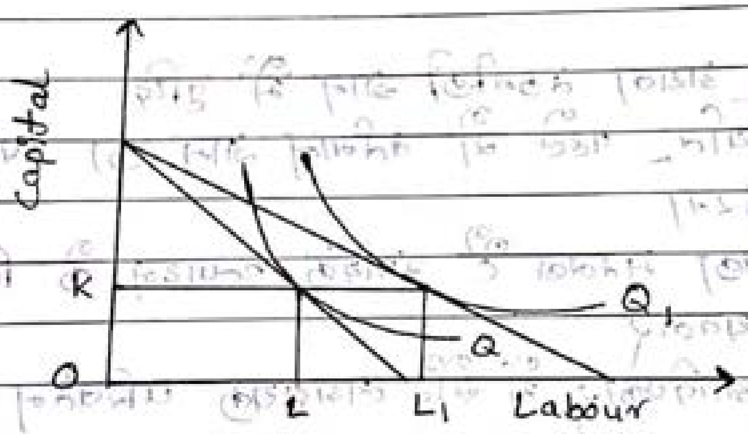

चित्र ①

अर्थव्यवस्था में पूँजी की OK मात्रा तथा श्रम की OL मात्रा रोजगार में लगा कर समभात्र वक्र Q द्वारा व्यक्त निर्गत का उत्पादन किया जा रहा था। अब नई तकनीक के साथ, पूँजी की वही OK मात्रा निर्गत के अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन में सहायक है जिसे अधिक ऊँची समभात्र Q_1 प्रकट करती है और साथ ही अधिक श्रम LL_1 उद्योग में लगती है। ऐसी तकनीकों को चाहिए कि कुशलता तथा पूँजी निर्माण के युगल उद्देश्य को पूरा करें। छोटी सिंचाई स्कीमों, अच्छे औजारों तथा उपकरणों के प्रसार, उतनी ही भूमि से अधिक उपज

देने वाली अल्पावधिक फसलों के प्रवर्तन, खाद तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। बर्ट होजलिट्स ने अनेक-शोध-पत्रों के आधार पर स्पष्ट किया है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासकीय रुकावटें लोगों को विवश करती हैं कि वे उत्पादन की उत्पादन वर्धक विधियों की बजाय पुरानी तकनीकों के प्रयोग को अधिमान दें।

आधुनिक पूँजी-गहन तकनीकि
(Capital-intensive modern techniques) =

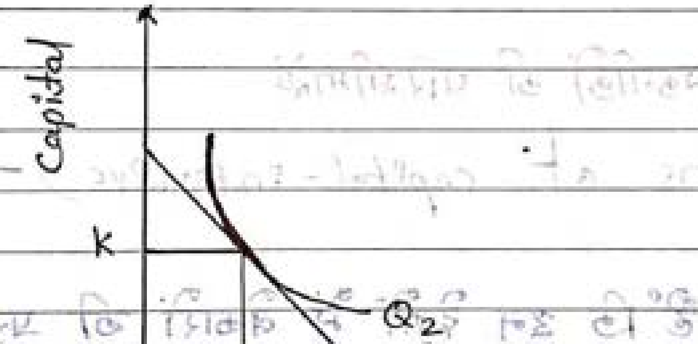

सामान्य रूप से दूसरा विकल्प यह सुझाया जाता है कि पूँजी-गहन तकनीकों का प्रयोग किया जाए। क्योंकि अल्पविकसित देश उन्नत देशों के प्रौद्योगिकीय विकास के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें चाहिए कि उन्नत देशों की प्रौद्योगिकी का विस्तृत पैमाने पर प्रयोग करें।

उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रकट करता है जो कि पूँजी गहन है। यह OL श्रम के अनुपात में अधिक पूँजी OK का प्रयोग करती है। इस कल्पना से कि सममात्रा वक्र Q_2 चित्र (1)

के Q, से ऊपर है, उस तकनीक में उत्पादन का स्तर अधिक ऊँचा है।

गैलेन्सन तथा लीबन्स्टीन → "सफल आर्थिक विकास, विशिष्ट रूप में पूर्ण पिछड़ेपन के रहते हुए, इस बात पर निर्भर रहता है कि जितने बड़े पैमाने पर सम्भव हो सके, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रवर्तन किया जाए।"

आय पर "सतत तथा संयोजन प्रभाव" के लिए उन्नत तकनीकें अनिवार्य समझी जाती हैं। फिर उनका प्रयोग, परम्परागत कार्यकारी आदतों, जीवन-स्थितियों, तथा लोगों के पूर्ण दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में सहायक होगा।

पूँजी-गहन तकनीकों की परिसीमाएँ

(Limitations of capital-intensive) -

① सभी जानते हैं कि इन देशों में बेकारों की प्रचुरता और पूँजी की अत्यन्त कमी होती है, पर आधुनिक प्रौद्योगिकी अत्यन्त पूँजी गहन तथा श्रम-बचतकारी है।

② आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए अत्यन्त कुशल, तकनीकी तथा प्रबन्धक सेविवर्ग की पूरक पूर्तियों की भी आवश्यकता रहती है, जो कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उपलब्ध नहीं होती।

③ ऐसी प्रौद्योगिकी के प्रवर्तन की सम्भावना अल्पविकसित देशों में पहले से प्रचलित और विदेश से आयातित तकनीकों को पृथक करने वाले अन्तर "प्रौद्योगिकी प्रसार" पर निर्भर रहेगी।

(5) सबसे बढ़कर आधुनिक प्रौद्योगिकी का अपनाना विद्युत-~~सेवाओं के~~ शक्ति, परिवहन तथा संचार सुविधाओं, अत्यन्त प्रशिक्षित तकनीकी सेवियों तथा बहुत अधिक संख्या में सम्बद्ध-सेवाओं के अस्तित्व की पूर्वकल्पना कर लेता है, जो अल्पविकसित देशों में नहीं होती।

Unit-II

Theories of Development:-

The Marxian Model मार्क्स का सिद्धान्त

कार्ल मार्क्स ने आर्थिक विकास में तीन प्रकार की सैद्धान्तिक व्याख्या दी।

① इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या -
(Materialistic Interpretation of History)

समाज के विभिन्न वर्गों में लगातार संघर्ष पाया जाता है यह ऐतिहासिक कारण से होता है।

इस संघर्ष का कारण उत्पादन की विधि है। इसी प्रकार उत्पादन का सम्बन्ध विरोध का कारण है।

सामाजिक ढाँचा दो प्रकार से समूह का योग है -

① पूँजीपति वर्ग
② सर्वाहारा वर्ग

उत्पादन का ढाँचा इस वर्ग संघर्ष का कारण है इससे सामाजिक प्रणाली नष्ट हो जाती है।

② ✓ अतिरेक मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Surplus Value) -

कार्लमार्क्स ने M-C-M' मॉडल दिया जिसमें कम मुद्रा M लेकर साधनों द्वारा C वस्तु बनाई जाती है और उसे अधिक मुद्रा M' में बेचा जाता है।

अर्थात M < M' से यही अतिरेक (अधिक) मूल्य है यह अतिरेक मूल्य शर्त की सहायता से तैयार होता है।

उदाहरण:- एक मजदूर 10 घण्टे कार्य करता है परन्तु उसे निर्वाह के लिए 6 घण्टे का श्रम जरूरी है तो उसे 6 घण्टे श्रम के बराबर मजदूरी दी जाती है। बचा हुआ 4 घण्टे श्रम का मूल्य पूँजीपति की जेब में जाता है। यही अतिरेक मूल्य है।

2013 → अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त को समझाइए। (2M), 2018 (2M)
2014 → मार्क्स की शोषण दर क्या है। (2M), 2013 (3M)
2015 → मार्क्स की लाभ की दर क्या है? (3M)

③ पूँजी संचय का सिद्धान्त – यह अतिरिक्त मूल्य या लाभ से ही पूँजी संचय होता है मार्क्स का विचार है कि अतिरिक्त लाभ से पूँजी का संचय होता है। इससे पूँजीपति का लाभ बढ़ता है इसके उपाय हैं –

① कार्य का घण्टा बढ़ाकर
② स्त्रियों और बच्चों को काम पर लगाकर
③ मजदूरी घटाकर

पूँजी की मात्रा से लाभ का निर्धारण होता है इसे निम्न सूत्र से बताया गया

वस्तु का कुल मूल्य = स्थिर पूँजी + परिवर्तनशील पूँजी + अतिरिक्त मूल्य

| कुल मूल्य = c + v + s | = (c + v) + s

इस प्रकार मार्क्स ने पूँजी को दो भाग में बताया (c + v)
इस तरह मार्क्स ने पूँजी को स्थिर पूँजी तथा परिवर्तनशील पूँजी में विभक्त किया है। स्थिर पूँजी (c) वह है जो श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है यथा – मशीन, उपकरण, यन्त्र आदि। मजदूरी अथवा श्रम-शक्ति को खरीदने में लगी पूँजी को मार्क्स ने परिवर्तनशील पूँजी (v) कहा है। अतिरिक्त मूल्य को (s) द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

कार्लमार्क्स के अन्य सिद्धान्त

① लाभ की दर की घटती प्रवृत्ति – मार्क्स ने बताया कि लाभ की दर और पूँजी की संगठित रचना में विपरीत संबंध पाया जाता है। पूँजी की संगठित संरचना में स्थिर पूँजी (c) को परिवर्तनशील पूँजी (v) द्वारा भाग दिया जाता है।
अतः स्पष्ट है कि c/v बढ़ने से लाभ की दर कम होगी।
पूँजी संचय का दुष्परिणाम होता है कि बेरोजगारी बढ़ती जाती है।

(2) पूंजी संचय का परिणाम – पूंजी संचय के फलस्वरूप भारी उद्योगों में पूंजी का केन्द्रीकरण होने लगता है। पूंजीपतियों के बीच प्रतियोगिता उन्हें अपनी वस्तुओं का मूल्य घटाने पर विवश करती है। वे पूंजीपति जो उन्नत तकनीक का प्रयोग नहीं करते और श्रम बचतकारी मशीनों का प्रयोग नहीं करते, बाहर धकेल दिए जाते हैं और बड़े पूंजीपति उनके उद्यमों को हथिया लेते हैं।

(3) पूंजीवादी संकट – मार्क्स का कथन है कि पूंजीवादी प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह भी है कि वस्तुओं के उत्पादन पर तो ध्यान केन्द्रित रखा जाता है, परन्तु उपभोग पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसका कारण यह है कि पूंजीपति का लक्ष्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है चाहे वह उसे उत्पादन में वृद्धि के जरिए प्राप्त करे अथवा श्रमिकों की मजदूरी में कटौती करके। उत्पादन में वृद्धि के लिए वह नई मशीनों का प्रयोग करता है जिससे छोटे उद्योग वाले श्रमिकों का कार्य ठप हो जाने से वे बेरोजगार तो हो ही जाते हैं साथ ही उन्नत मशीनों के कारण भी कारखाने में अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिकों को कम मजदूरी मिलना और उनमें बेरोजगारी होना, आदि।

(4) उत्पादन के साधन – मार्क्स उत्पत्ति के साधनों में श्रम, पूंजी, साहस व संगठन को सम्मिलित करते हैं, परन्तु उनके अनुसार श्रम उत्पत्ति का एक सर्वोपरि व महत्वपूर्ण साधन है और सम्पूर्ण आर्थिक उत्पादन का आधार है।

(5) निवेश – मार्क्स का मत था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश लाभ से प्रेरित होता है। लाभ की अधिक सम्भावना होने पर पूंजीपति अधिक मात्रा में निवेश को तत्पर होता है। निवेश वृद्धि से पूंजीपति को दो तरह का लाभ प्राप्त होता है।

2017 → मार्क्स के विकास सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (5M), 2012

① निवेश में वृद्धि से एक तरफ लाभ की मात्रा में वृद्धि होती है। जो
② दूसरी तरफ अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि होती है।

✓ सिद्धान्त की आलोचनाएँ

① वास्तविकता से विपरीत – मार्क्स का सिद्धान्त वास्तविकता से विपरीत माना जाता है, क्योंकि मशीनें अल्पकाल में बेरोजगारी उत्पन्न करती हैं, परन्तु दीर्घकाल में स्थिति में सुधार हो जाता है।

② स्थैतिक विश्लेषण – मार्क्स आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन जिन औजारों (मूल्य का श्रम सिद्धान्त तथा मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धान्त) की सहायता से करते हैं वे अनिवार्य रूप से स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त थे न कि प्रावैगिक आर्थिक विश्लेषण के लिए।

③ श्रमिक संघर्ष – समाजवादी राष्ट्रों में भी श्रमिक स्वयं संघर्ष करते हैं तथा राजनीतिज्ञ ही बड़े पूंजीपति का रूप धारण कर लेते हैं।

④ समाजवाद व पूंजीवाद का सम्बन्ध – मार्क्स का विचार था कि पूंजीवाद के चरम विकास की अवस्था में पहुँच जाने पर ही समाजवाद का उदय होगा, परन्तु वास्तव में समाजवाद इन राष्ट्रों में आया है, जहां पूंजीवाद उदय भी नहीं हुआ है।

⑤ जनसंख्या सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण विचार – मार्क्स जनसंख्या को भी पूंजीवाद की समस्या मानते थे, परन्तु आज समाजवादी राष्ट्रों में भी जनसंख्या नियन्त्रण पर विचार किया जाता है।

(6) एकाधिकार का अभाव – मार्क्स का विचार था कि पूंजीवाद में एकाधिकार की स्थापना की जाती है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि समस्त राष्ट्रों में एकाधिकार की स्थापना ही हो।

(7) सिद्धांत का अभाव – आलोचकों का विचार है कि मार्क्स अर्थशास्त्री नहीं थे तथा उनके द्वारा कोई सिद्धान्त ही नहीं दिया गया।

निष्कर्ष :
"औपचारिक मॉडल के रूप में मार्क्स का अर्थशास्त्र निर्बल है। जिन आन्तरिक विरोधों का यह प्रणाली उद्देश्यपूर्वक विश्लेषण करती है, वे पूंजीवाद के होने की अपेक्षा मार्क्स की प्रणाली के ही साधक हैं।"

2017 → शुम्पीटर का विकास मॉडल क्या है? बताइए। (5M)
2019 → नवप्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? (5M) 2013 (2M)

The Schumpeterian Model

शुम्पीटर का विकास सिद्धांत — नवप्रवर्तन

जोसेफ एलोई शुम्पीटर (J. A. Schumpeter) (1911) ने जर्मनी में यह सिद्धांत दिया। जे॰ए॰ शुम्पीटर ने प्रथम बार सन् 1911 में जर्मन भाषा में प्रकाशित "The Theory of Economic Development" में अपना सिद्धान्त प्रस्तुत किया। इसका अंग्रेजी संस्करण 1934 में प्रकाशित हुआ। बाद में व्यापार चक्र Business Cycles (1939), Capitalism, Socialism and Democracy पूंजीवाद, समाजवाद एवं प्रजातन्त्र (1942) में इस सिद्धान्त को परिष्कृत एवं परिवर्धित किया गया परन्तु इसकी आधारभूत विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

शुम्पीटर का विश्लेषण

अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह –
सिद्धान्त :- अर्थव्यवस्था में आर्थिक कार्य की पुनरावृत्ति रक्त प्रवाह के समान एक ही गति से होती है।

आर्थिक विकास का अर्थ (Meaning of Economic Development) – नवप्रवर्तन के कारण होने वाले असतत परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं।

नवप्रवर्तन (Innovations) – उत्पादन की नई तकनीक, नए आविष्कार को नवप्रवर्तन कहते हैं।

नवप्रवर्तनों के स्वरूप :-
1. किसी नवीन वस्तु का उत्पादन करना
2. उत्पादन की नई तकनीक
3. नए बाजारों की खोज होना
4. कच्चे माल के नए पूर्ति-स्रोतों का पता लगाना
5. एकाधिकार स्थापित करने की तरह किसी उद्योग के नए संगठन की कार्यान्वित करना।

नवप्रवर्तक का कार्य (Role of Innovator) – शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास का कार्य स्वतः नहीं होता बल्कि उस कार्य को विशेष प्रयास व जोखिमों के साथ शुरू करना होता है। यह कार्य नवप्रवर्तक अर्थात् उद्यमी करता है, पूंजीपति नहीं। पूंजीपति केवल पूंजी प्रदान करता है जबकि उद्यमी उसके प्रयोग का निर्देशन करता है। शुम्पीटर का कहना है कि "आदमी के सम्बन्ध में स्वामित्व नहीं बल्कि नेतृत्व अधिक महत्वपूर्ण होता है।"

नवप्रवर्तक की प्रेरणा :-

1. नवीन वाणिज्य साम्राज्य की स्थापना।
2. श्रेष्ठता की इच्छा।
3. प्रवीणता पर खुश होना।

पूंजी, लाभ एवं ब्याज (Capital, Profit and Interest) -
शुम्पीटर के अनुसार पूंजी केवल वह स्त्र है जिसके द्वारा उद्यमी जिन वस्तुओं को चाहता है, उनको अपने नियन्त्रण में रखता है। लाभ लागतों के ऊपर आधिक्य है जो कुल प्राप्तियों एवं लागतों का अन्तर है। पूंजी और लाभ की तरह, शुम्पीटर ब्याज को भी विकास की देन मानता है।

विकास मॉडल :- (चक्रीय प्रक्रिया)

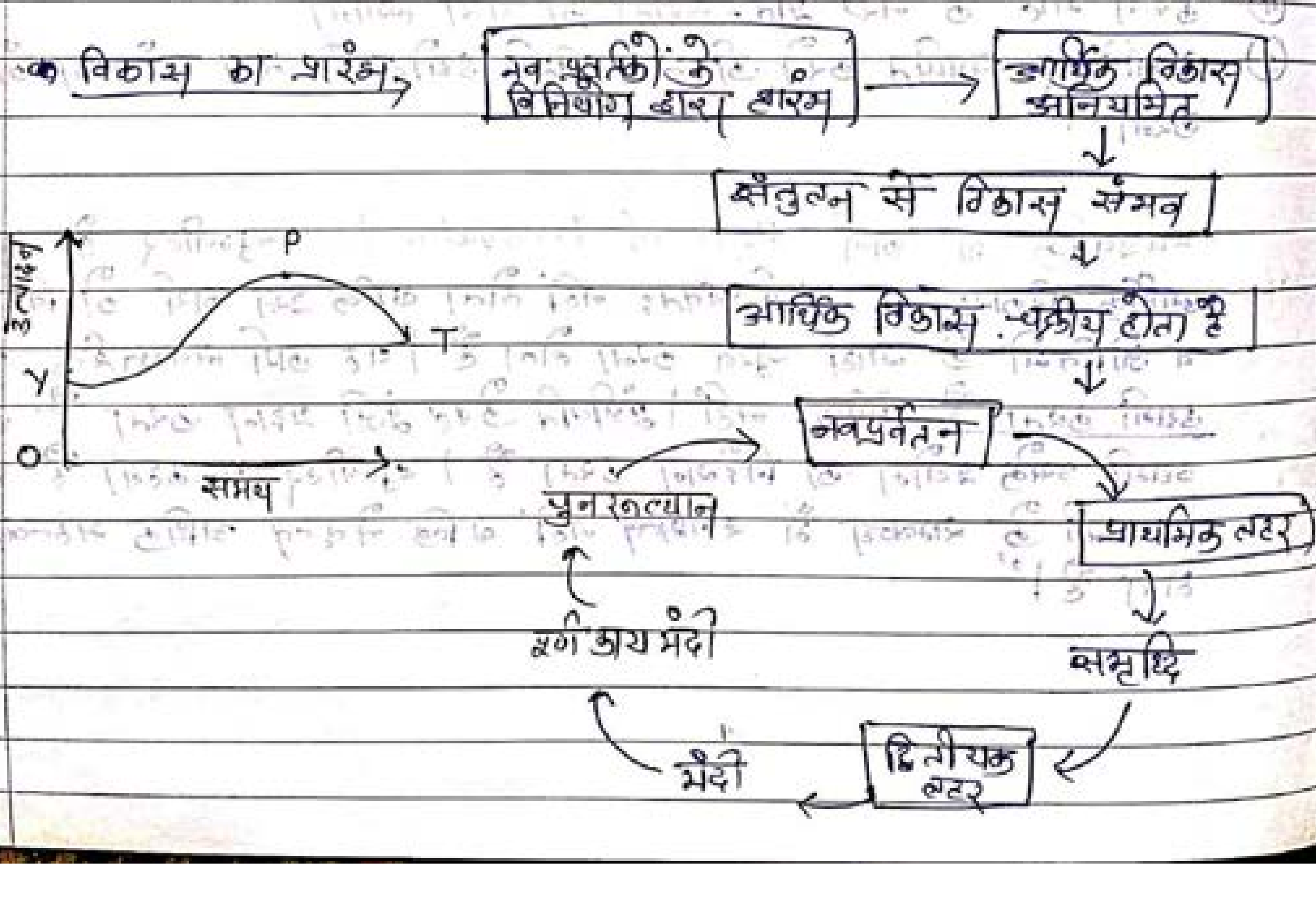

शुम्पीटर के सिद्धान्त की मुख्य बातें

(Main features of Schumpeter's Theory)

(1) साहसी को महत्व दिया गया है।
(2) विकास हेतु पर्याप्त पूंजी जरूरी है।
(3) चित्र प्रवाह तोड़ने साख जरूरी है।
(4) नव प्रवर्तन से विकास होता है।
(5) लाभ महत्वपूर्ण है।
(6) नवीन तकनीक से विकास होता है।
(7) आर्थिक विकास व आर्थिक प्रगति होता है।

पूंजीवाद के विनाश की प्रक्रिया

(Process of end of capitalism)

पूंजीवाद का अंत जरूर होगा। पूंजीवाद स्वयं अपने विनाश हेतु जिम्मेदार है। पूंजीवाद धीरे² समाप्त होगा। इसके 3 कारण हैं:-

(1) उद्यमी अर्थ में ह्रास
(2) समृद्ध परिवारों में बिखराव
(3) पूंजीवादी ढांचे का विघटन

आलोचनाएँ (Criticism)

(1) नव प्रवर्तन नहीं समाज के सामूहिक प्रयासों से विकास होता है।
(2) विकास कोई चक्रीय क्रिया नहीं है।
(3) नव प्रवर्तन व्यापार चक्र से संबंधित नहीं है।
(4) पूंजीवाद से समाजवाद की ओर गमन करने की शुम्पीटर धारणा उचित नहीं है।
(5) नवप्रवर्तन की अनियमितता की व्याख्या नहीं की गयी है।
(6) लाभ का शून्य होना अस्पष्ट है।

२०१७ कीन्स के विकास सिद्धान्त को समझाइए। (5M)

Keynesian Theory of Development

केन्ज़ीय सिद्धान्त

प्रो. जे. एम कीन्स ने अपना विकास का सिद्धान्त पूँजीवादी देशों से सम्बन्धित बताया। प्रो. केन्स ने सन 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "The General Theory of Employment, Interest and Money" में स्पष्ट किया कि समाज में रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर रहती है। यदि वस्तुओं और सेवाओं की प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो जाती है तो रोजगार की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है जिसके फलस्वरूप समाज की कुल आय में वृद्धि होती है।

केन्स का सिद्धान्त

किसी देश की कुल आय उसके रोजगार का फलन होती है।

$$Y = f(N)$$

Y = कुल आय
f = फलन
N = रोजगार की मात्रा

किन्स के अनुसार वास्तविक माँग रोजगार व आय के बीच संतुलन स्थापित करती है।

वास्तविक माँग की स्थिति में कुल माँग कीमत = कुल पूर्ति कीमत होता है।

त्रुटि

किन्स ने अपने सिद्धान्त में आर्थिक विकास का अलग से सिद्धान्त नहीं दिया।

केन्स का रोजगार सिद्धान्त

रोजगार का स्तर = उत्पादन की मात्रा = राष्ट्रीय आय

↓

प्रभावपूर्ण माँग

- कुल माँग फलन (ADF)
  - उपभोग फलन
    - आय का आकार स्थिर
    - उपभोग प्रवृत्ति
      - औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) (अल्पकाल: स्थिर)
      - सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) → गुणक
  - विनियोग फलन
    - पूँजी की सीमान्त क्षमता (MEC)
      - पूँजीगत सम्पत्ति की पूर्ति कीमत
      - पूँजीगत सम्पत्ति सम्भावित आय
    - ब्याज की दर
      - मुद्रा की माँग → तरलता पसन्दगी
        - लेन देन उद्देश्य
        - सुरक्षा उद्देश्य
        - सट्टा उद्देश्य
      - मुद्रा की पूर्ति (स्थिर)
- कुल पूर्ति फलन (ASF) स्थिर

मान्यताएँ (Assumptions)

कीन्स का रोजगार सिद्धान्त निम्नांकित मान्यताओं पर आधारित है:

(1) कीन्स का सिद्धान्त अल्पकालीन है क्योंकि कीन्स के अनुसार दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे।

(2) यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लेकर चला है।

(3) कीन्स का सिद्धान्त एक बन्द अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है।

(4) उत्पादन में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है।

(5) मुद्रा विनिमय का ही नहीं अपितु 'मूल्य संचय' का माध्यम भी है।

(6) अर्थव्यवस्था में 'अनैच्छिक बेरोजगारी' उपस्थित रहती है।

अल्पविकसित देशों पर केन्ज़ के सिद्धान्त की व्यवहार्यता

(Applicability of Keyne's Theory to underdeveloped countries)

(1) चक्रीय बेरोजगारी के कारण यह सिद्धान्त विकासशील देशों पर लागू नहीं होता।

(2) किन्स का अर्थशास्त्र केवल अल्पकालीन होता है परन्तु विकास दीर्घकालीन होता है अतः इस सिद्धान्त की उपादेयता कम है।

(3) बन्द अर्थव्यवस्था इन देशों में नहीं पायी जाती।

(4) इन देशों में आर्थिक क्रिया स्थैतिक होती है अतः यह सिद्धान्त कम व्यवहारिक है।

2015 → रोस्टोव की विकास अवस्थाओं के नाम बताइये। (2M)

Rostow's Stages of Economic Growth.

रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं
1960 में W.W. Rostow's ने The stages of economic growth में आर्थिक वृद्धि की उल्लेख किया।

सिद्धांत :-
रोस्टोव के अनुसार आर्थिक वृद्धि की पाँच अवस्थाएँ है

विकास की अवस्थाएँ (5M)

- परम्परागत समाज
- उत्कृष्ट की पूर्व की अवस्था
- उत्कृष्ट की अवस्था
- परिपक्वता की ओर अग्रसर
- अत्यधिक उपभोग की अवस्था

① परम्परागत समाज (The Traditional Society)

① इस अवस्था में सीमित उत्पादन फलन पर आधारित था।
② इसका विकास न्यूटन पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित था।
③ सामाजिक ढाँचा उत्तराधिकारी था।
④ परिवार और जाति प्रमुख थे।
(5) सत्ता भूमिपति और पूँजीपति के हाथ में थी।
(6) 75% जनसंख्या कृषि आधारित थी।
(7) कृषि आय का प्रमुख साधन था।
(8) आय का अपव्यय सामाजिक आर्थिक धारणाएं से होता था।

(2) उत्कर्ष की पूर्व अवस्था -

(1) यह अवस्था एक संक्रमण काल है।

(2) इसमें सतत विकास की पूर्व अवस्था बनती है।

(3) यूरोप में 15वीं शताब्दी में आया।

(4) यह अवस्था मध्ययुग की समाप्ति और आधुनिक युग की आरम्भ में आयी।

(5) यह अवस्था चार कारणों से आयी।

(i) नवजागरण

(ii) नवराजतंत्र

(iii) नवजगत

(iv) नवधर्म

इसी युग में सामान्तवाद का अंत हुआ।

(6) परम्परागत समाज से उत्कर्ष के पूर्व की अवस्था से दूसरी अवस्था आने की प्रक्रिया निम्नानुसार है -

[आर्थिक प्रगति का विचार आता है] → [निजी क्षेत्र में / सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोगी] → [बचत जुटाते हैं] →

[लाभ व आधुनिकीकरण] → [बैंकिंग संस्थाओं का उदय] →

[आन्तरिक व बाह्य व्यापार में वृद्धि] → [निर्माणकारी उद्योग आते हैं]

इस स्थिति की तीन दशाएँ रोस्टोव ने ~~[illegible]~~ बताया।

(1) सामाजिक ऊपरी पूँजी का निर्माण हो।

(2) कृषि उत्पादकता बढ़े

(3) आयातों का विस्तार हो।

(3) उत्कर्ष की अवस्था (The Take-off Stage) -

ब्रिटेन 1783, फ्रांस 1830, अमेरिका 1843, जापान 1878, रूस 1917

चीन व भारत 1952 में आत्मस्फूर्ति की अवस्था में आया।

उत्कर्ष की शर्तें

(1) उत्पादन व विनियोग दर की राष्ट्रीय आय से 5% से बढ़ाकर 10% करना।

(2) निर्माण क्षेत्रों का विकास:

(i) प्राथमिक क्षेत्र (ii) सहायक क्षेत्र (iii) व्युत्पन्न क्षेत्र

(3) राजनैतिक, सामाजिक और संस्थागत ढाँचे के साथ सांस्कृतिक ढाँचे का विस्तार हो।

इस प्रकार उत्कर्ष का सूत्रपात तीव्र प्रोत्साहन के कारण होता है और आगे निवेश अनुपात बढ़कर राष्ट्रीय आय के 10% से अधिक पर चल जाती है।

(4) परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था

"वह अवधि है, जब कोई समाज अपने अधिकतर साधनों पर (तत्कालीन) आधुनिक प्रौद्योगिकी के रेंज का प्रभावपूर्ण व्यवहार करती है।" यह दीर्घ सतत आर्थिक वृद्धि की अवधि होती है, जो चार दशाब्दियों से भी अधिक समय तक रहती है। पुरानी उत्पादन तकनीकों का स्थान नई उत्पादन तकनीकें ले लेती हैं। नए प्रमुख क्षेत्रों का निर्माण होता है। शुद्ध निवेश की दर राष्ट्रीय आय के 10% से अधिक के आसपास होती है और अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित झटके सहन कर सकती है।

ब्रिटेन	1850	स्वीडन	1930
अमेरिका (संयुक्त राज्य)	1900	जापान	1940
जर्मनी	1910	रूस	1950
फ्रांस	1910	कनाडा	1950

जब कोई देश प्रौद्योगिकीय परिपक्वता की अवस्था में होता है, तो तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं:

① कार्यकारी शक्ति की प्रकृति में परिवर्तन :- कार्यकारी शक्ति की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। वह प्रयुक्ततया कुशल बन जाती है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की बजाय शहरी क्षेत्रों में रहना पसन्द करते हैं। वास्तविक मजदूरी बढ़ने लगती है और अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए श्रमिक अपना संगठन करते हैं।

② उद्यमता की प्रकृति में परिवर्तन :- उद्यमता की प्रकृति बदलती है। कठोर तथा परिश्रमी मालिकों का स्थान सभ्य तथा विनम्र प्रबंधकर्ता ले लेते हैं।

③ नई आवश्यकताएं :- (New wants) :- औद्योगीकरण के चमत्कारों से समाज ऊब जाता है और कुछ नया चाहता है, जो और परिवर्तन लाए।

⑤ अत्यधिक उपभोग की अवस्था
(The Age of high mass Consumption)

उपनगरों में स्थानान्तरण तथा मोटरगाड़ियों, टिकाऊ उपभोक्ता-वस्तुओं और घरेलू मशीन पुर्जों का अधिक प्रयोग, अत्यधिक उपभोग के युग की विशिष्टता प्रदान करते हैं।

- समाज का ध्यान पूर्ति की अपेक्षा माँग पर,
- उत्पादन की समस्याओं की अपेक्षा उपभोग पर,
- विस्तृत अर्थ में कल्याण की समस्याओं पर अधिक बढ़ जाता है।

① राष्ट्रीय सीमाओं के परे तक शक्ति तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नीति का अनुसरण।

② प्रगतिशील कराधान और कार्यकारी शक्ति के लिए बढ़ रही सामाजिक सुरक्षा

तथा अवकाश के माध्यम से राष्ट्रीय आय के अपेक्षाकृत अधिक उचित वितरण के द्वारा कल्याणकारी राज्य लाना।

(3) नए व्यापार केन्द्र तथा प्रमुख क्षेत्रों जैसे सस्ती मोटरगाड़ियां, मकान तथा बिजली से चलने वाले अनेक यंत्रों आदि का निर्माण करने का निर्णय।

आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं की आलोचना (book)

(Criticisms of the stages of Growth)

1. विकास के लिए परम्परागत समाज का पाया जाना आवश्यक नहीं।
2. यह आवश्यक नहीं कि पूर्व स्थितियां उत्कर्ष से पहले आएं।
3. अवस्थाओं में परस्पर व्यापी -

Unit-III

Approaches to Development:-

2017 → श्रम की असीमित पूर्ति सिद्धान्त को समझाइए। (उत्तर)
2013 → 2015 → आर्थर लेविस के असीमित श्रम पूर्ति सिद्धान्त को समझाइए। (उत्तर)

Arther Lewis Model of Unlimited Supply of Labour

आर्थर लुईस का असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धान्त

प्रो॰ आर्थर लुइस ने अपने लेख "Economic Development with Unlimited Supply of Labour" → विकास की प्रक्रिया पर विचार किया। (1954)

- आर्थर लुइस ने श्रम की असीमित पूर्तियों से आर्थिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
- उन्होंने कृषि क्षेत्र में श्रम की अधिकता की मान्यता लेकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास की व्याख्या की है।

कथन:- "निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ण लोचदार पूर्ति का परम्परावादी मॉडल अनेक अविकसित देशों में भी सही ठहरता है।"

द्वि-क्षेत्र अर्थव्यवस्था:-

(i) पूंजीवादी क्षेत्र (उद्योग)
(ii) जीवन निर्वाह क्षेत्र (कृषि)

* मॉडल के अनुसार- (विकास प्रक्रिया)
जीवन निर्वाह क्षेत्र में प्रचलित जीवन निर्वाह स्तरीय मजदूरी दर पर
→ श्रम की पूर्ति > श्रम की मांग, इस श्रम अतिरेक को जीवन

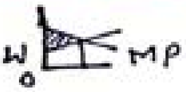

$S_L > D_L$

~~निर्वाह स्तरीय मजदूरी दर दूसरी जगह लगाया जा सकता है।~~
~~व्यवहार में पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी दर निर्वाह मजदूरी दर से 30%~~
~~अधिक होती है।~~
~~अर्थात् श्रम की MP > मजदूरी दर अतिरेक को → परिसंपत्तियों~~
~~में निवेश → पूंजी निर्माण ⇒ आर्थिक विकास की प्रक्रिया उस समय~~
~~रुकेगी जब श्रम अतिरेक शेष नहीं रहेगा जिसे रोजगार पर~~
~~लगाया जा सके।~~

(4)

OS = निर्वाह मजदूरी
OW = पूंजीवादी मजदूरी
WW = पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम पूर्ति वक्र
SS पूर्ति वक्र

✓ लुईस मॉडल की व्याख्या:-

(1). केन्द्रीय समस्या (श्रम शक्ति का एकीकरण):-
* अल्पविकसित देशों में प्रचलित मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति पूर्णतया लोचदार (असीमित)
- आवश्यकता से अधिक श्रम
- कृषि पर बढ़ती निर्भरता
- अदृश्य बेरोजगारी

(2) समस्या का समाधान (श्रम शक्ति का उचित प्रयोग)
अल्पविकसित देशों की प्रमुख समस्या उस बेकार श्रम शक्ति का उचित ढंग से प्रयोग करने की है। लुईस अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटता है-
(A) पूंजीवादी क्षेत्र:- पूंजीगत साधनों का प्रयोग पूंजीपति की भुगतान
(B) जीवन निर्वाह क्षेत्र:- पूंजीगत साधनों का प्रयोग नहीं

अपेक्षाकृत प्रति व्यक्ति उत्पादन कम

लुईस के अनुसार

जीवन निर्वाह क्षेत्र से श्रमिक हटाकर → पूंजीवादी क्षेत्र में → नए उद्योग या वर्तमान उद्योगों का विस्तार → रोजगार ↑ राष्ट्रीय आय ↑ आर्थिक विकास होगा

③ पूंजीवादी अतिरेक :-

जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों की मजदूरी दर, पूंजीवादी क्षेत्र में श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम सीमा होती है। दोनों क्षेत्रों की मजदूरी दर में सामान्यतः 30% या अधिक का अंतर होता है।

पूंजीवादी क्षेत्र में ऊंची मजदूरी दर के कारण :-

(i) जीवन स्तर की बढ़ती लागतें (मानवतावादी दृष्टिकोण)
(ii) श्रम संघ - सौदेबाजी
(iii) श्रमिक वर्ग द्वारा भी अधिक मजदूरी पर जोर
(iv) पूंजीवादी क्षेत्र में काम के लिए अधिक मजदूरी की मांग

④ पूंजी निर्माण : पूंजीवादी अतिरेक पर निर्भर (विकास प्रक्रिया) :-

प्रो॰ लुईस के अनुसार पूंजीवादी क्षेत्र में अतिरेक को नई परिसंपत्तियों में निवेश करने से पूंजी निर्माण होगा जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा रोजगार ↑ पूंजीवादी अतिरेक ↑ पूंजी निर्माण ↑ अर्थात् आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ

चित्र

⑤ राज्य तथा निजी पूंजीपतियों की भूमिका :-

अर्द्धविकसित देशों में बचत कम होती है क्योंकि -

(A) उपभोग व्यय अधिक (निवेश की तुलना में)
- व्यापारी, भूमिपति, राजा महाराजा

(5) पूंजीवादी लाभ का राष्ट्रीय अनुपात कम
- वेतन / मजदूरी वर्ग 3% बचत

(6) बैंक साख द्वारा पूंजी निर्माण :-
- साख सृजन द्वारा भी पूंजी निर्माण उत्पादन एवं रोजगार स्तर ↑
* लुईस मानता है कि इससे मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो सकती है किन्तु दीर्घकाल में इससे कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि -
(i) प्रारंभिक अवस्था में आय ↑ उपभोग उत्पादन ↑ कीमतें ↓
(ii) सरकार (राज्य) को करारोपण से आय वितरण प्रबन्धन नहीं करना पड़ेगा।

(7) विकास प्रक्रिया का अन्त :-
जैसे-जैसे पूंजी निर्माण ↑ उत्पादन ↑ रोजगार ↑ लाभ ↑ → लाभ का निवेश
↓
पुनः पूंजी निर्माण ↑

इसी प्रकार आर्थिक विकास का क्रम चलता रहता है परंतु विकास की यह प्रक्रिया निम्न परिस्थितियों में रुक जाती है -
(i) पूंजी निर्माण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त श्रम नहीं बचता
(ii) निर्वाह क्षेत्र में नई तकनीकी का प्रयोग
(iii) व्यापार की शर्तें पूंजीवादी क्षेत्र के प्रतिकूल (श्रमिकों को अधिक मजदूरी)
(iv) निर्वाह क्षेत्र में श्रम की AP बढ़ जाए → पूंजीवादी क्षेत्र में W↑ लाभ ↓

मान्यताएं
(1) अर्थव्यवस्था में असीमित श्रम पूर्ति विद्यमान है।
(2) अर्थव्यवस्था द्वि क्षेत्रीय है, पूंजीवादी क्षेत्र तथा जीवन निर्वाह क्षेत्र।
(3) अर्थव्यवस्था में उपलब्ध श्रम सामान्यतया अकुशल प्रकार का होता है।
(4) पूंजीपतियों द्वारा लाभ के विनियोग के कारण पूंजी का संग्रह होता है।
(5) जीवन निर्वाह क्षेत्र में पूंजीवादी क्षेत्र की अपेक्षा प्रति व्यक्ति उपज कम होती है।

(6) पूँजीवादी क्षेत्र में विनियोग उत्पादकता वृद्धि के अनुपात में कम होता है।
(7) पूँजीवादी क्षेत्र में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी निश्चित एवं समान होनी चाहिए।
(8) श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की लागत एकसमान बनी रहनी चाहिए।

समीक्षात्मक मूल्यांकन / आलोचना

(1) अवास्तविक मान्यता
(2) यदि पूँजी संचय श्रम बचतकारी है तो यह सिद्धान्त लागू नहीं होता
(3) उद्यमशीलता का अभाव
(4) आय वितरण असमानता
(5) श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य नहीं होती
(6) कुल माँग की उपेक्षा
(7) श्रम की गतिशीलता सहज नहीं
(8) अकुशल कर प्रशासन

(1) सीमित क्षेत्र
(2) पूँजीवादी क्षेत्र में श्रम का स्थानांतरण कठिन
(3) श्रम शक्ति को प्रशिक्षण में अधिक समय
(4) निवेश गुणक की क्रियाशीलता का अभाव
(5) बचत केवल पूँजीवादी क्षेत्र के लोग नहीं करते
(6) अन्य विकसित देशों में मान्यताओं का अभाव
(7) जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी नहीं

Ranis & Fie Model (55)
(The Fei - Ranis Theory of Dual Economy)

फाई - रेनिस का दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धान्त

2019 → रेनिस एवं फाई मॉडल को समझाइए (5M), 2018

Introduction :-

फाई व रेनिस ने 'A Theory of Economic Development' शीर्षक वाले एक लेख में विश्लेषण किया है कि संक्रमण प्रक्रिया में एक विकासशील अर्थव्यवस्था गतिहीनता की स्थिति से आत्मजनक वृद्धि की ओर जाने की आशा करती है।

सिद्धान्त :- (The Theory) -

① विकासशील श्रम अतिरेक
② संसाधनहीन अर्थव्यवस्था

जिसमें अधिकतर जनसंख्या विस्तृत बेरोजगारी और जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दरों के बीच कृषि में कार्यरत है। कृषि अर्थव्यवस्था गतिहीन है। लोग पारम्परिक कृषि व्यवसायों में संलग्न हैं। कृषि रहित व्यवसाय पाए जाते हैं किन्तु उनमें पूँजी का कम उपयोग होता है, इसमें एक सक्रिय तथा गत्यात्मक औद्योगिक क्षेत्र भी है। विकास से अभिप्राय कृषि अतिरेक श्रमिकों का औद्योगिक क्षेत्र को पुनः आवंटन करना है, जिनका कृषि उत्पादन में योगदान शून्य अथवा नगण्य है, जहां वे कृषि में संस्थानिक मजदूरी के बराबर मजदूरी पर उत्पादक बन जाते हैं।

मान्यताएं (Assumptions) :-

① यह एक दोहरी अर्थव्यवस्था है, जिसमें प्रथम परम्परागत तथा गतिहीन कृषि क्षेत्र है और द्वितीय एक सक्रिय औद्योगिक क्षेत्र।
② कृषि क्षेत्र का उत्पादन केवल भूमि तथा श्रम का फलन है।
③ भूमि के सुधार के अतिरिक्त कृषि में पूँजी का संचय नहीं होता है।
④ भूमि की पूर्ति स्थिर है।
⑤ कृषि कार्य में पैमाने के स्थिर प्रतिफल पाए जाते हैं जिनमें श्रम एक परिवर्ती साधन है।
⑥ दोनों क्षेत्रों में श्रमिक केवल कृषि वस्तुओं का उपभोग करते हैं।
⑦ औद्योगिक क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी स्थिर रहती है।

फाई तथा रेनिस श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था के विकास को तीन अवस्थाओं में प्रस्तुत करते हैं।

प्रथम अवस्था → अदृश्य बेरोजगार श्रमिक जो कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं करते, को निरन्तर संस्थानिक मजदूरी पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

द्वितीय अवस्था → कृषि श्रमिक जो कृषि उत्पादन में वृद्धि तो करते हैं किन्तु प्राप्त संस्थानिक मजदूरी से कम उत्पादन करते हैं, ऐसे श्रमिक भी औद्योगिक क्षेत्र में भेज दिए जाते हैं। यदि श्रमिकों का औद्योगिक क्षेत्र में निरन्तर स्थानान्तरण किया जाता रहता है तो अन्ततः ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब खेतीहर श्रमिक संस्थानिक मजदूरी के बराबर उत्पादन करते हैं।

तृतीय अवस्था → उत्कृष (take off) की अन्तिम स्थिति है और आत्मजनक वृद्धि का प्रारम्भ है, जबकि खेतीहर मजदूर संस्थानिक मजदूरी

से अधिक उत्पादन करने लगते हैं। इस अवस्था में श्रम अतिरेक समाप्त हो जाता है और कृषि का व्यापारीकरण हो जाता है।

(A)

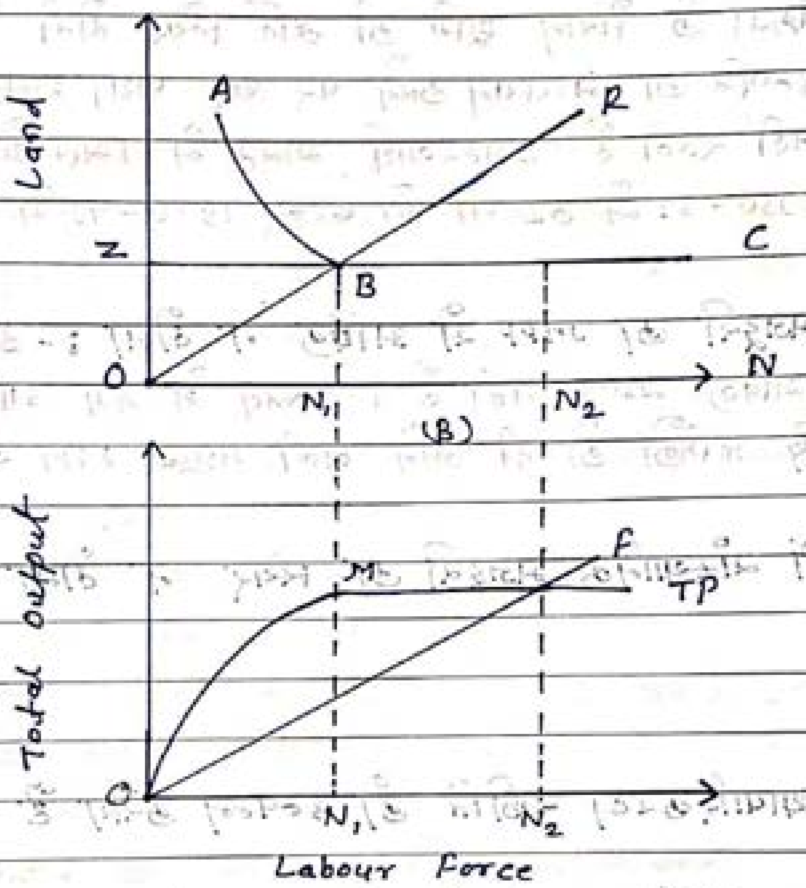

(A) कृषि की प्रक्रिया - श्रम (L) तथा भूमि (Z) द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। श्रम का माप अनुलम्ब अक्ष तथा भूमि को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया गया है। किरण OR उत्पादन की अवस्था दर्शाती है। वक्र ABC कृषि वस्तुओं की उत्पादन परिधि रेखा है। भूमि को OZ पर स्थिर मानकर श्रम ON, अधिकतम उत्पादन करता है।

समीक्षात्मक मूल्यांकन (Critical Appraisal)

① भूमि की पूर्ति का स्थिर न होना :- फाई तथा रेनिस यह धारणा लेकर चले है कि विकास प्रक्रिया के दौरान भूमि की पूर्ति स्थिर होती है। दीर्घ अवधि में फसल एकड़ उत्पत्ति का अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि भूमि की मात्रा स्थिर नहीं रहती है। उदाहरणार्थ, भारत में फसल क्षेत्र का सूचकांक (आधार 1961-62) 1950-51 में 82 था जो बढ़कर 1970-71 में 107.3 हो गया।

② संस्थानिक मजदूरी का MPP से अधिक न होना :- इस मान्यता के पक्ष में कोई आनुमानिक प्रमाण नहीं है। वास्तव में श्रम अतिरेक अल्पविकसित देशों में कृषि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी MPP से काफी कम होती है।

③ कृषि क्षेत्र में संस्थानिक मजदूरी का स्थिर न होना

④ बंद मॉडल

⑤ कृषि का व्यापारिकरण स्फीति को उत्पन्न करता है

⑥ MPP शून्य नहीं है - भूमि की स्थिर मात्रा के साथ जनसंख्या का एक बहुत बड़ा आकार होगा जो MPP को शून्य बनाएगा। शुल्ज इस मत से सहमत नहीं है कि श्रम-अतिरेक अर्थव्यवस्थाओं में MPP शून्य है।

2014 → लेबिन्स्टीन के आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
2013 → न्यूनतम क्रांतिक प्रयास क्या है? (3M)
2015, 2016 → न्यूनतम प्रयास सिद्धान्त, 2019 (3M)

Leibenstein's Critical Minimum Effort thesis

लीबन्स्टीन का क्रांतिक-न्यूनतम प्रयत्न सिद्धान्त

लीबन्स्टीन का सिद्धान्त :-

प्रो. हार्वे लीबिन्स्टीन ने अपनी पुस्तक 'Economic Backwardness and Economic Growth' में यह विचार प्रकट किया है कि अल्प विकसित देशों में दरिद्रता का दुश्चक्र पाया जाता है, जो उन्हें प्रति व्यक्ति निम्न आय सन्तुलन की स्थिति के आस-पास बनाए रखता है।

लीबिन्स्टीन का मत है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था 'झटकों' तथा 'प्रोत्साहनों' के अधीन काम करती है।
'झटका' - प्रति व्यक्ति आय को घटाने का प्रभाव है,
'प्रोत्साहन' - उसे बढ़ाने में सहायक है।

विश्व में कुछ देश इस कारण अल्प विकसित रहे हैं कि वहां प्रोत्साहनों का आकार थोड़ा रहा और झटकों का आकार अधिक रहा है। अतः आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि आवश्यक न्यूनतम प्रयास द्वारा झटकों के आकार को कम किया जाय और प्रोत्साहनों को बढ़ाया जाय। आवश्यक न्यूनतम प्रयास द्वारा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस परिस्थिति में आय बढ़ाने वाले साधनों की अपेक्षा, आयवर्द्धक साधन अधिक प्रेरित होंगे। लीबिन्स्टीन ने यह विचार भारत, इण्डोनेशिया जैसे अर्द्ध विकसित देशों की समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात प्रकट किए हैं।

मॉडल :-

(1) (i) पिछड़ेपन से मुक्ति - इसमें पिछड़ेपन से मुक्ति प्राप्त करने के प्रयासों का अध्ययन किया गया।

(ii) समस्याओं का अध्ययन - इसमें समस्याओं के निराकरण के स्थान पर समस्याओं को समझने का अध्ययन किया गया।

(iii) विकास का प्रयास - इसमें विकास के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रयासों को समझाया गया है।

(2) विशेषताएं -

1. कृषि की विशेषताएं
2. सांस्कृतिक व राजनीतिक विशेषताएं
3. तकनीकी व अन्य विशेषताएं
4. जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएं
5. अन्य आर्थिक विशेषताएं।

(3) सिद्धान्त - देश में प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक न्यूनतम मात्रा से कम विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए जिससे आय में वृद्धि होकर बचत बढ़े व आर्थिक दुश्चक्र समाप्त हो जाए। विनियोजन की मात्रा को एक वर्ष में करने के स्थान पर उसे 8-10 वर्षों में फैलाकर विनियोजन करना चाहिए तथा हर विनियोजन की न्यूनतम मात्रा का एक अनुकूलतम स्तर होना चाहिए।

(4) आवश्यकता -

(1) सन्तुलित विकास - इस अवस्था में देश में सन्तुलित विकास सम्भव किया जा सकता है। न्यूनतम आवश्यक प्रयास की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं और प्रत्येक चरण में न्यूनतम विनियोजन के द्वारा यह प्रयास सुलभ हो सकता है कि आर्थिक विकास शनैः शनैः सन्तुलन की ओर बढ़ता चले।

सन्तुलित विकास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रयास ही एकमात्र उपाय है।

(ii) प्राचीन प्रथाओं की समाप्ति (दर) में प्राचीन प्रथाओं की समाप्ति के लिए न्यूनतम विनियोजन आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है कि पुरानी विचारधारा, रीति रिवाज तथा अवस्थाओं को समाप्त करके नए विचारों के अनुसार विकास कार्य किया जाए जिसके लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयास ही एकमात्र आश्रय है। इससे कम विनियोजन से विकास में सफलता नहीं मिलती है।

(iii) बाह्य मितव्ययिताएं - बड़ी मात्रा में विनियोजन से ही बाह्य मितव्ययिताएं प्राप्त की जा सकती हैं।

(iv) बाधाओं को हटाना - विकास के परिणामस्वरूप जो बाधाएं उपस्थित हों, उन्हें दूर करने के लिए न्यूनतम विनियोजन आवश्यक है। प्रत्येक अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्था में दो तत्व विद्यमान होते हैं - एक तो प्रोत्साहनवर्द्धक तथा दूसरे बाधामूलक तत्व।

मॉडल की त्रुटियां
1. जनसंख्या वृद्धि दर एवं मरण दर से असंबंधित
2. आय बढ़ने के साथ जनसंख्या का बढ़ना
3. जन्म दर में कमी तर्कपूर्ण नहीं है
4. राज्य प्रयासों की उपेक्षा
5. समय तत्वों की व्याख्या नहीं
6. बन्द अर्थव्यवस्था
7. प्रति व्यक्ति आय तथा वृद्धि दर में जटिल सम्बन्ध

2015, 2017

2019 → प्रबल प्रयास सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (5M)

2018 → बड़े धक्के का सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं? (3M)

2016 → big push Theory

The Big push theory.

"बड़ा धक्का" सिद्धान्त / प्रबल प्रयास

रोजेन्स्टीन - रोडान की थीसिस

(Rosenstein Rodan's Thesis)

'प्रबल प्रयास' सिद्धान्त प्रो॰ पाल॰ एन॰ रोजेन्स्टीन - रोडान के नाम से सम्बन्धित है। इस थीसिस का सार यह है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में विकास की बाधाओं को पार करने एवं उसे प्रगति पथ पर लाने के लिए 'प्रबल प्रयास' की आवश्यकता है, जो निश्चित न्यूनतम, परन्तु उच्च मात्रा के विनियोग के रूप में हों।

"यदि विकास प्रोग्राम को थोड़ा भी सफल बनाना है, तो संसाधनों का एक न्यूनतम स्तर, उस प्रोग्राम में लगाना ही पड़ेगा। किसी देश को वृद्धि की आत्मनिर्भरता की अवस्था में लाना ठीक ऐसा ही है - जैसे हवाई जहाज को धरती से हवा में उड़ाना। भूमि पर एक ऐसी क्रान्तिक - गति होती है, जिसे विमान को वायुवाहित बनने के लिए धरती पर ही पार करना पड़ता है।"

बड़े धक्के का सिद्धान्त निम्न तीन अविभाज्यताओं तथा बाह्य मितव्ययिताओं पर आधारित है:-

1. माँग की अविभाज्यता
2. उत्पादन फलन की अविभाज्यता
3. बचत की पूर्ति में अविभाज्यता

* यह सिद्धान्त 'संतुलित वृद्धि सिद्धांत' पर आधारित है।

मान्यताएं :-

(i) अल्पविकसित देशों में न्यूनतम स्तर विद्यमान
(ii) विकास के लिए न्यूनतम आवश्यक निवेश
(iii) बड़े धक्के से बाह्य बचतों की प्राप्ति
(iv) सरकार को आर्थिक संरचना के निर्माण हेतु पर्याप्त निवेश कर देना चाहिए।
(v) अल्पविकसित देशों में बाह्य मितव्ययिताओं का अभाव
(vi) अर्थव्यवस्था में अविभाज्यताएं तथा अपूर्णताएं पाई जाती हैं।
(vii) 'संतुलित वृद्धि' व्यूह रचना आवश्यक

सिद्धान्त की व्याख्या

(1) बड़े धक्के से बाह्य मितव्ययिताओं का विकास :-
- अल्पविकसित देशों में आर्थिक एवं सामाजिक संरचना का अभाव → निजी निवेश की प्रेरणा नहीं
- यदि सरकार न्यूनतम निवेश ↑ बाह्य मितव्ययिता ↑
- नए साहसी उपक्रम लगाना प्रारंभ करेंगे
- उपक्रमों का विस्तार (नए स्थानों पर)
- घरेलू / विदेशी पूंजी निवेश ↑ (∵ लाभ अधिक)

(2) बाजार विस्तार :-
निवेश ↑ पूर्ति पक्ष का विस्तार होने से मांग पक्ष में विस्तार भी जारी इससे सहायक एवं पूरक उद्योगों का विकास → अन्तर उद्योग मांग का विस्तार → विकास में गति आय का सृजन → मांग ↑ उद्योग की पूर्ण क्षमता का प्रयोग होगा → लागत न्यूनतम स्तर पर

(3) अविभाज्यताएं तथा बाह्य बचतें:

(i) उत्पादन फलन में अविभाज्यताएँ -
- सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यता (परिवहन, संचार, शक्ति, जल, थल, सड़के, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य)
- ये आवश्यक व्यय है
- नहीं तो तकनीकी लाभ नहीं होंगी
- इनका आयात संभव नहीं

(ii) माँग की अविभाज्यताएं -
- माँग अथवा पूरक माँग की अविभाज्यताएं
- परस्पर निर्भर उद्योगों का विकास एक साथ ताकि माँग में कमी की समस्या न हो
- एक साथ निवेश ↑ माँग ↑ रोजगार ↑ राष्ट्रीय आय ↑

eg: रोडान ने जूते के कारखाने का उदाहरण दिया

कारखाने में एक प्रच्छन्न बेरोजगारों को काम, इनकी मजदूरी से अतिरिक्त आय का सृजन यदि आय को जूतों की खरीदने पर व्यय करेंगे तो जूता बाजार में निरंतर माँग रहेगी → जूता उद्योग सफल. लेकिन समस्त आय जूतों पर व्यय नहीं करेंगे क्योंकि मानव की अन्य भी बहुत सी आवश्यकताएं होती है। कारखाने के बाहर के लोग भी इन अतिरिक्त जूतों को नहीं खरीदेंगे क्योंकि वे दरिद्र है। इनके पास धन का अभाव होता है और अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होते है।

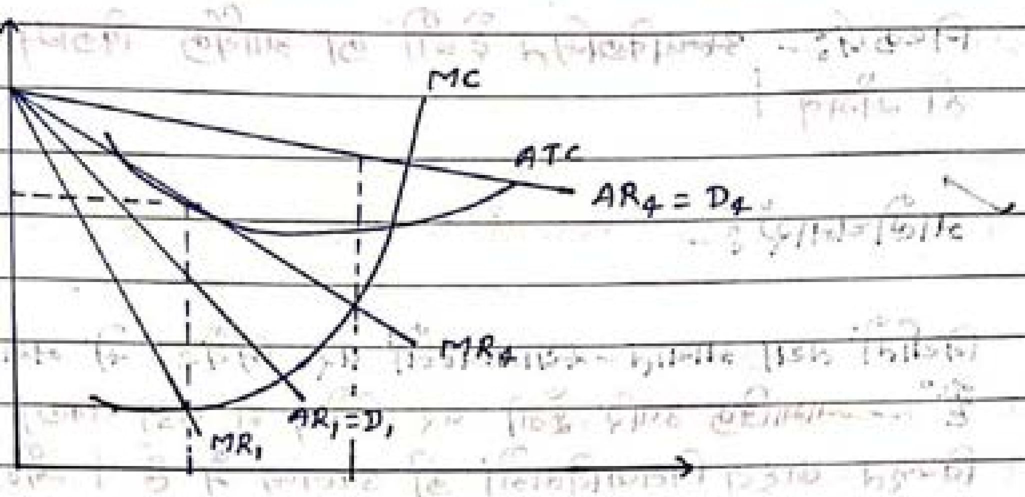

(iii) बचत की पूर्ति में अविभाज्यता :-
आय के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के पश्चात् बचतों में वृद्धि संभव
बचतों में वृद्धि के लिए → विनियोगों में वृद्धि

(iv) मनोवैज्ञानिक अविभाज्यता :-
इनके अनुसार मनोवैज्ञानिक तत्व (बल, प्रेरणा) और अनुकूल वातावरण भी विकास के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी न्यूनतम निवेश मात्रा।

(4) संतुलित विकास के संतुलनों का अध्ययन :-
(i) उपभोक्ता द्वारा माँग में वृद्धि करने पर विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों में क्षैतिज संतुलन लाना
D↑ S↑

(ii) सामाजिक ऊपरी व्यय (SOC) एवं प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं में संतुलन
(iii) पूंजीगत उद्योगों और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में उनकी तकनीकी निर्भरता के अनुसार उर्ध्वाधर संतुलन जिससे बड़े पैमाने पर बाह्य बचतें प्राप्त हों।

निष्कर्ष :- अल्पविकसित देशों का आर्थिक विकास संतुलित विकास द्वारा ही संभव।

आलोचनाएं :-

① निर्यातों तथा आयात - स्थानापन्नों पर निवेश से नगण्य मितव्ययिताएं होती हैं - सामाजिक उपरि पूँजी पर निवेश में 'बड़ा धक्का' की प्रमुख सार्थकता विस्तृत बाह्य मितव्ययिताओं की उपलब्धि में है। प्रो० जैकब वाइनर - अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं, घरेलू निवेशों से स्वतन्त्र रहकर ही विश्व बाजार से बहुत बड़ी मितव्ययिताएं प्राप्त कर लेती हैं। रोडन स्वीकार - नए-नए विकासशील देशों में निर्यात तथा सीमान्त आयात - स्थानापन्नों के लिए निवेश कुल निवेश के बड़े अंश को प्राप्त कर लेता है। 'बड़ा प्रयास' के लिए बाह्य मितव्ययिताएं नगण्य हैं।

② कृषि विकास पर कम महत्व :- औद्योगिक प्रगति से ही देश का आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है। इस विकास में कृषि का कोई योगदान नहीं होता है। कृषि प्रधानता बनी रहने के कारण कृषि के विकास के बिना आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकता। कृषि के लिए आवश्यक विनियोग भूमि सुधार, सिंचाई, अच्छे खाद व बीज की उपलब्धि, उन्नत यन्त्रों के प्रयोग में किया जा सकता है और इससे आर्थिक विकास का आधार बनता है। 'बड़े धक्के' के सिद्धान्त में कृषि के विकास के लिए भी अधिक विनियोजन की बात कही गई है।

③ बचतों का शून्य होना :- अर्द्ध विकसित देशों के सन्दर्भ में 'प्रबल प्रयास' के सिद्धान्त में यह कमी प्रतीत होती है कि इन देशों में जहां पूंजी का अभाव पाया जाता है, वहां बचतें भी प्रारम्भिक अवस्था में शून्यप्राय होती हैं। इस बात का महत्व इस सिद्धान्त में अच्छी प्रकार नहीं समझा गया।

(4) अवास्तविकताओं पर आधारित :- विकासशील देशों के लिए यह लागू नहीं हो सकता। इतिहास साक्षी है कि आज के विकसित देशों का विकास प्रबल प्रयास के सहारे नहीं हुआ है। इन देशों ने आर्थिक प्रगति शनैः शनैः की है। यह ऐतिहासिक तथ्य है।

(5) कम विनियोजन अर्थव्यवस्था :- आर्थिक विकास के लिए कम विनियोजन अर्थव्यवस्था को अधिक सन्तुलित बना सकता है। इस बात के प्रमाण नहीं मिलते कि अर्द्ध विकसित देशों के लिए 'प्रबल प्रयास' का सिद्धान्त अपरिहार्य है। इसके बिना प्रगति हो ही नहीं सकती।

(6) सरकारी नियोजन पर बल :- रोडान ने अर्द्ध विकसित देशों के निजी पूँजी के अभाव की समस्या के समाधान के लिए सरकारी विनियोजन की बात पर बल दिया है। इन देशों में अधिकांशतः मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिलता है और राज्य पर विनियोजन के लिए निर्भर होने पर विभिन्न प्रकार की प्रशासकीय तथा संस्थागत कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। साथ ही निजी तथा सरकारी विनियोजन में प्रतियोगिता की भावना बनी रहती है। अतः 'प्रबल प्रयास' का सिद्धान्त अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

(7) ऐतिहासिक तथ्य का अभाव :- रोडान का यह सिद्धान्त अल्प विकसित देशों की शीघ्र प्रगति के मार्ग पर चलने का एक नुस्खा है, परन्तु इस बात की ऐतिहासिक व्याख्या नहीं है कि यह विकास किस प्रकार का होता है। प्रो० हेगन का मत है कि "ऐतिहासिक दृष्टि से प्रबल प्रयास की उपस्थिति में कहीं भी विकास की प्रमुख विशेषता नहीं पाई जाती है।"

Unit - IV

Development Models :-

The Limits to Growth Model

सीमाबद्ध वृद्धि मॉडल

Introduction :-

- 1968 में रोम क्लब नाम की संस्था विश्व के 75 व्यक्तियों के ग्रुप द्वारा स्थापित की गई जो समाज के विभिन्न वर्गों से संबंध रखते हैं। जून 1970 में क्लब का उद्देश्य "मानवजाति की भविष्यवाणी" रखा गया।
- 1972 में डोनल्ड मीडोस (Donald Meadows) के नेतृत्व में MIT के चार वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया जिसे रोम क्लब ने The Limits to Growth नाम रिपोर्ट में प्रकाशित किया।

क्लब ने 1992 में Beyond the Limits → दूसरी रिपोर्ट → जिसमें ताजा प्रमाणों के आधार पर बताया गया कि कैसे मानव जाति सीमाओं से आगे निकल चुकी है। वैज्ञानिकों के अतिरिक्त विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी सीमाबद्ध वृद्धि संबंधी विचार आर्थिक वृद्धि की लागतों के रूप में व्यक्त किए हैं।

आर्थिक वृद्धि की लागतें (Costs of Economic Growth) :-

मिशान ने आर्थिक वृद्धि की लागतें (1967) शब्द प्रयोग किए हैं। परंपरागत अर्थशास्त्रियों माल्थस, रिकार्डो तथा मिल के समय से आधुनिक अर्थशास्त्री गालब्रेथ, मिशान आदि ने आर्थिक वृद्धि से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों के संबंध में आवाज बुलंद की है। आर्थिक वृद्धि के उद्देश्यों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन की गुणवत्ता ऋणात्मक रूप से प्रभावित हुई है, पर्यावरण प्रदूषित हुआ है,

प्राकृतिक साधनों का अपक्षय हुआ है तथा उससे सामाजिक - आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में असफलता प्राप्त हुई है।

सीमाबद्ध वृद्धि मॉडल का विश्लेषण

(Analysis of the Limits to Growth Model)

- 1971 में MIT के J. Forrester ने अपनी पुस्तक World Dynamics में एक मॉडल की रचना की जिसमें आधुनिक चरों जैसे विश्व जनसंख्या, विश्व औद्योगिक उत्पादन, खाद्यान्न पूर्ति, प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों के पारस्परिक प्रभावों की जाँच की गई। रोम क्लब के वैज्ञानिकों ने फौरेस्टर की गत्यात्मक प्रणाली का प्रयोग करते हुए एक विस्तृत कम्प्यूटर मॉडल की रचना की।

✓ " निरंतर वृद्धि से अनन्त मात्राएं पैदा होती हैं जो एक सीमित विश्व में उपयुक्त नहीं बैठती हैं।

- इस धारणा को एक कठिन मॉडल के रूप में विकसित किया गया है जिसकी समीकरण के रूप में सरलता से व्याख्या नहीं की जा सकती है। ऐसा इस कारण कि 5 चरों के बीच संबंध एकरेखात्मक नहीं है और इनसे संबंधित गुणांक 5 चरों के स्तर पर निर्भर करते हैं - जनसंख्या, खाद्यान्न, उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, अनवीनीकरण संसाधन, तथा प्रदूषण।

✓ ये घटक नए संसाधनों के प्रयोग, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी निर्देश देते हैं।

मॉडल की भविष्यवाणियां (Predications of the Model)

① चरों में घातांकीय वृद्धि - भविष्य में प्रमुख विश्व जनसंख्या स्तर, खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन में घातांकीय वृद्धि होगी। यदि इस घातांकीय वृद्धि को रोका न गया तो भूमण्डल में विनाश का दृश्य होगा।

② अनवीनीकरण संसाधनों पर नियंत्रण - भविष्य में प्रमुख अनवीनीकरण संसाधनों में तांबा, स्वर्ण, सीसा, मरकरी (पारा), प्राकृतिक गैस एवं तेल, चांदी, टीन एवं जिंक के भण्डार समाप्त हो जायेंगे। इसलिए इनका विदोहन विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए।

③ तकनीकी प्रगति - भविष्य में तकनीकी प्रगति से भौतिक स्रोतों को अनन्त काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः भावी वृद्धि को सावधानीपूर्वक सीमाबद्ध किया जाए अन्यथा आने वाले 50 अथवा 100 वर्ष विनाश के होंगे।

④ पृथ्वी पर दबाव - भूमंडल पर जीवन समाप्त हो जायेगा क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि, अनवीनीकरण संसाधनों की मात्रा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जायेगी और जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि से पृथ्वी की क्षमता पर दबाव बढ़ जायेगा।

⑤ वैश्वी संतुलन को कायम रखना - इस विनाश को समय से पहले रोका जा सकता है यदि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर तथा बढ़ते प्रदूषण स्तर पर रोक लगाकर शून्य वृद्धि के साथ वैश्वी संतुलन को कायम किया जाए।

मॉडल की रेखाचित्र द्वारा व्याख्या

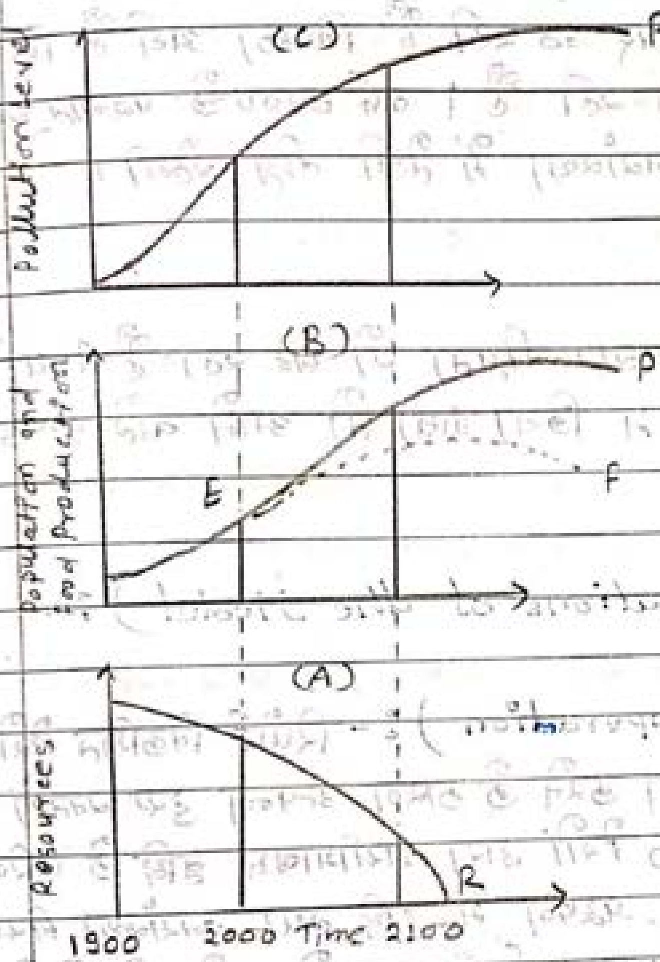

(A) समय → वर्ष 1900 से 2100 (क्षैतिज अक्ष)

संसाधनों → अनुलंब अक्ष

संसाधन वक्र R बाएं से दांए नीचे की ओर ढलान लिए है और यह संकेत कर रहा है कि अनवीनीकरणीय संसाधन (जैसे तेल भण्डार, प्राकृतिक गैस, तांबा, सीसा आदि) सीमित मात्रा में हैं तथा उनका विदोहन अत्यधिक होने से वर्ष 2100 तक भण्डार लगभग समाप्त हो जायेंगे।

(B) अनुलंब अक्ष → जनसंख्या तथा खाद्यान्न प्रति

P → जनसंख्या

वक्र F → खाद्यान्न प्रति

वर्ष 2000 तक दोनों में वृद्धि होती है। लेकिन बिंदु C के पश्चात वक्र P तेजी से ऊपर उठ रहा है जो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि वक्र F की ढलान धीरे-धीरे ऊपर उठ रही है जिसका अर्थ है कि खाद्यान्न पदार्थों में घटते क्रम से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2100 के पश्चात खाद्यान्न उत्पादन तेजी से घटेगी, जबकि जनसंख्या में तेजी तीव्र रहेगी।

(c) प्रदूषण स्तर → PN वक्र
जिसका स्तर वर्ष 2000 के पश्चात तीव्रता से बढ़ रहा है। यदि समयानुसार प्रदूषण को नियंत्रित न किया गया तो आने वाले 50 अथवा 100 वर्ष विनाश के होंगे।

मॉडल के निहित तत्व (Implications of the Model) :-

① सार्वजनिक सहयोग (Public Cooperation) :- रिपोर्ट विकसित देशों द्वारा भौतिक संपदा का अत्याधिक अनुसरण करने के कारण उत्पन्न हुए खतरों को उजागर करती है। विकसित औद्योगिक देशों द्वारा असीमाबद्ध वृद्धि के परिणाम, अनवीनीकरण संसाधनों के विदोहन, प्रदूषण में वृद्धि तथा जनसंख्या विस्फोट के परिणामों के संदर्भ में चेतावनी तथा सार्वजनिक सहयोग से इन्हें रोकने के लिए आग्रह करती है।

② समाधान (Solutions) :- रिपोर्ट प्रदूषण संरक्षण, अनवीनीकरण संसाधनों के विवेकपूर्ण विदोहन तथा जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लागू करने के सुझाव देती है। अन्यथा विश्व के सामने आने वाले 50 अथवा 100 वर्ष विनाश के हो सकते हैं।

③ शून्य वृद्धि दर (Zero Growth Rate) :- सीमाबद्ध वृद्धि मॉडल का एक अन्य महत्वपूर्ण नीति निर्देश यह है कि सरकारों को ऐच्छिक रूप से एक शून्य वृद्धि दर नीति अपनानी चाहिए।

सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Model) :-

① स्थिर आरक्षित सूचक :- सीमाबद्ध वृद्धि मॉडल की आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह अनवीनीकरण संसाधनों को दुर्लभ मानता है और उनके अनुसार वर्ष 2100 तक लगभग समाप्त हो जायेंगे। मॉडल स्थिर आरक्षित अधिसूचक का प्रयोग करता है, जो कि वर्तमान उपभोग का वर्तमान आरक्षित संसाधनों का अनुपात है।

② तकनीकी विकास :- यह मॉडल तकनीकी विकास के योगदान के बारे में कोई वर्णन नहीं करता है। तकनीकी विकास से अनवीनीकरण संसाधनों को कम लागत पर निकालना संभव हुआ है। तकनीकी विकास के कारण नए संसाधनों, जैसे परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस आदि स्रोतों का विकास हुआ है।

③ खाद्यान्न उत्पादन :- कृषि योग्य भूमि सीमित मात्रा में है और भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट होगी। कान्ह (H. Kahn) का मत है कि अब भी विश्व निश्चित सीमाबद्ध वृद्धि की अवस्था को पार कर जायेगा, नई अथवा वैकल्पिक प्रौद्योगिकी सब सीमाओं को हटा देगी तथा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ेगा।

④ जनसंख्या वृद्धि :- मॉडल भविष्यवाणी करता है कि जनसंख्या घातांकीय दर से बढ़ेगी। वर्ष 2000 तक विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन हो जायेगी। यदि जन्म दर कम न हो और मृत्यु दर में लगातार (कमी) हो तो यह वर्ष 2030 तक 14.4 बिलियन हो जायेगी। लेकिन विश्व की जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। यह वर्ष 2000 तक 6 बिलियन ही रही।

⑤ प्रदूषण :- मॉडल यह मानकर चलता है कि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि तथा विकास के साथ प्रदूषण का स्तर घातांकीय दर से बढ़ेगा जिससे मानव के जीवन स्तर तथा अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रदूषण एक गम्भीर समस्या है फिर भी विकसित एवं विकासशील देशों में इसे नियंत्रित करने के लिए साफ प्रौद्योगिकी

का प्रयोग किया जा रहा है।

⑥ कीमत प्रणाली :- यह मॉडल बाजार प्रणाली की गहनता तथा कीमत हेतु की अवहेलना करता है।

⑦ शून्य वृद्धि दर :- सीमाबद्ध मॉडल प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शून्य वृद्धि दर की नीति का सुझाव देता है। वृद्धि समर्थक अर्थशास्त्री इस नीति का विरोध करते हैं। उनके अनुसार यदि सकारात्मक वृद्धि दर से विनाश होता है तो शून्य वृद्धि दर से विनाश उससे भी अधिक और शीघ्र होगा।

Myrdal's Theory of Circular Causation.

मिर्डल का चक्रीय कार्यकारण का सिद्धान्त

2019
2013 → मिर्डल के चक्रीय कार्यकरण सिद्धान्त को समझाइए। (3M)

Introduction :-

प्रो० मिर्डल का कहना है कि आर्थिक विकास का परिणाम चक्रीय कार्यकरण प्रक्रिया होती है जिससे धनिकों को अधिक लाभ होता है और जो पिछड़ जाते हैं उनके प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। अतिनिर्यात प्रभाव अधिकार जमा लेते हैं और प्रसरण प्रभाव मन्द हो जाते हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय असमानताएँ संचयी रूप से बढ़ने लगती हैं और अल्पविकसित देशों के भीतर प्रादेशिक असमानताएँ भी आ जाती हैं।

अल्पविकसित देशों में चक्रीय एवं संचयी प्रक्रिया, जिसे 'दरिद्रता का कुचक्र' भी कहते हैं, नीचे की ओर परिचालन करती है और अनियमित होने के कारण बढ़ती असमानताएँ लाती है।

G. Myrdal, Economic Theory and Underdevelop Regions, 1957

मिर्डल का थीसिस (The Myrdal Thesis)

2016 → सन्तुलित एवं असन्तुलित विकास सम्बन्धित विवाद का वर्णन कीजिए। इनका समायोजन किस प्रकार किया जा सकता है?
2015 → सन्तुलित विकास को परिभाषित कीजिए। (2M) 2015
2016 → सन्तुलित विकास के घटकों की व्याख्या कीजिए।

The doctrine of Balanced Growth.

सन्तुलित विकास सिद्धान्त

Meaning of Balanced Growth.

सन्तुलित विकास का अर्थ किसी अर्थव्यवस्था का समस्त क्षेत्रों तथा उद्योगों का समान रूप से विकास करना अर्थात् उनमें एक साथ निवेश करना है।

Definitions

रैडावे के अनुसार, "सन्तुलित विकास का अर्थ अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में सन्तुलन स्थापित करने से है। इसके अन्तर्गत उत्पादन व उपभोग के मध्य, उपभोग क्षेत्र व पूंजी क्षेत्र के मध्य तथा उत्पादन प्रणाली में समन्वय स्थापित करना है जिससे कच्ची सामग्री, अर्द्ध निर्मित सामग्री एवं औद्योगिक आवश्यकताओं में सन्तुलन स्थापित किया जा सके।"

सन्तुलित विकास सिद्धान्त की व्याख्या

① रोजेन्स्टीन रोदान की व्याख्या :-

रोजेन्स्टीन रोदान ने 1943 ई. में प्रकाशित अपने लेख "Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe" में सन्तुलित विकास के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, परन्तु इन्होंने सन्तुलित विकास शब्द का प्रयोग नहीं किया। वे सन्तुलित विकास की नीति को एक 'बड़े धक्के' के रूप में प्रयोग करने के पक्षधर थे। बड़े धक्के से इनका तात्पर्य सभी क्षेत्रों में एक साथ और आवश्यक न्यूनतम मात्रा में विनियोग करना है।

② रैगनर नर्कसे की धारणा :-
नर्कसे ने 'से' के नियम से सन्तुलित वृद्धि के सिद्धान्त का सूत्र ग्रहण किया है और इस नियम में मिल के कथन का उल्लेख किया है "यदि समस्त प्रकार के उत्पादनों के मध्य, उत्पादन की प्रत्येक वृद्धि का ऐसे अनुपात में वितरण कर दिया जाए, जिसे निजी हित निश्चित करें, तो वह स्वयं अपनी माँग उत्पन्न ही नहीं, बल्कि संस्थापित कर लेती है।"
नर्कसे के अनुसार, अल्पविकसित देशों में दरिद्रता के दुश्चक्र कार्यशील रहते हैं जो आर्थिक विकास में बाधक होते हैं। पूर्ति एवं माँग दोनों पक्षों में दरिद्रता के दुश्चक्र चलते रहते हैं।

सन्तुलित विकास के प्रमुख तत्व / घटक

① बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोग - सन्तुलित विकास के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों का विकास किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी के विनियोग की आवश्यकता होती है।

② बाह्य मितव्ययताओं की प्राप्ति - एक उद्योग की बचत या उसका उत्पादन दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम में आ जाता है। उत्पादन इकाइयां बृहत् उत्पादन करने लगती हैं जिससे उनकी प्रति इकाई लागत कम होती है। आधारभूत उद्योगों के साथ कम महत्व के उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं और उनका विकास होने लगता है।

③ कुशल श्रम विभाजन :- सन्तुलित विकास होने से उत्पादन बृहत् पैमाने पर किया जाता है जिससे कुशल श्रम-विभाजन का विकास होता है। श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है तथा उत्पादन लागत में कमी आती है।

④ सामाजिक लाभों में वृद्धि :- मेयर एवं बाल्डविन का कहना है कि सन्तुलित विकास में निजी लाभ को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसमें सामाजिक

लाभ को ध्यान में रखा जाता है। इससे निजी लाभ व सामाजिक लाभ के अन्तर कम हो जाते हैं तथा सामाजिक लाभ का स्तर बढ़ जाता है।

(5) रोजगार अवसरों में वृद्धि :- सन्तुलित विकास बेरोजगार लोगों को कृषि के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कर रोजगार अवसरों में वृद्धि करता है।

(6) सर्वांगीण विकास :- प्रो० नर्कसे का कहना है कि सन्तुलित विकास से देश के सभी क्षेत्रों में विकास होता है चाहे वह क्षेत्र कृषि का हो या उद्योग का या शिक्षा के स्वरूप का या बैंक व परिवहन का।

(7) सन्तुलित विदेशी व्यापार - प्रो० नर्कसे का कहना है कि सन्तुलित विकास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुदृढ़ आधारशिला है। इसके कारण देश के विदेशी व्यापार में सन्तुलन बना रहता है।

सन्तुलित विकास की आलोचनाएं (criticism)

(1) अल्प विकसित देशों के लिए अनुपयुक्त :- सन्तुलित विकास के लिए जितनी पूँजी की आवश्यकता होती है उतनी पूंजी उन देशों के लिए जुटा पाना सम्भव नहीं होता है क्योंकि अल्प विकसित देशों में तो पहले से ही पूँजी का अभाव पाया जाता है।

(2) श्रम, पूंजी, साहस व संगठन की पूर्ति का अभाव :- सन्तुलित विकास में यह मान लिया जाता है कि अल्प विकसित देशों में श्रम, पूंजी, साहस व संगठन सभी की पूर्ति लोचदार होती है जबकि अल्प विकसित देशों में इनकी पूर्ति बेलोचदार होती है। इससे विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

(3) साधनों का अपव्यय :- जब सभी क्षेत्रों का विकास किया जाता है तो सम्भव है कि कुछ क्षेत्र सन्तोषजनक प्रगति न कर सकें। इससे साधनों का अपव्यय ही होता है।

(4) मुद्रा प्रसार की उत्पत्ति :- प्रायः यह देखा जाता है कि जो देश सन्तुलित विकास का मार्ग अपनाते हैं उनके यहां मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो उनके लिए हानिकारक ही होती है।

(5) योग्यता एवं कुशलता का अभाव :- सन्तुलित विकास के लिए योग्यता एवं कुशलता की पूर्ति प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है जबकि अल्प विकसित राष्ट्रों में इसको सीमित मात्रा में ही पाया जाता है।

(6) विनियोग का आधिक्य :- सन्तुलित विकास में विनियोग भारी मात्रा में किए जाते हैं जिससे विनियोग का आधिक्य हो जाता है तथा नवीन समस्याओं को जन्म मिल जाता है।

(7) सन्तुलित विकास निजी उपक्रम प्रणाली में सम्भव नहीं - सन्तुलित विकास निजी उपक्रम प्रणाली में सम्भव नहीं है।

(8) सन्तुलित विकास का सिद्धान्त अधूरा :- इस सिद्धान्त की आलोचना इस आधार पर भी की जाती कि यह सिद्धान्त अधूरा है। इसमें विकास मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, अभावों तथा क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(9) सन्तुलित विकास सिद्धान्त अनुपयुक्त एवं अव्यावहारिक -

2017 → असंतुलित विकास को परिभाषित कीजिए। (2M)
2018 → असंतुलित विकास का सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं? (3M)

The concept of Unbalanced Growth.

असन्तुलित विकास का अर्थ

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश न करके केवल कुछ क्षेत्रों में ही सर्वप्रथम निवेश किया जाना चाहिए, क्योंकि अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्था में साधन व पूंजी इतने नहीं होते कि समस्त क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जा सके।

अतः कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश करके उनसे विकास की गति तीव्र हो जाती है तथा अन्य क्षेत्रों का विकास किया जाता है। धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था असन्तुलित वृद्धि से सन्तुलित वृद्धि की ओर बढ़ती है।

Unit-V

Investment Criteria in Economic Development

विकासशील देशों में निवेश कसौटियों की आवश्यकता

NEED FOR INV. CRIT. IN. UD.C.

(अर्थ) निवेश की कसौटी = ऐसे दिशा निर्देश जो विकासशील देशों में अधिकरण द्वारा योजना के उद्देश्य के अनुसार अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की विनियोग के आवंटन हेतु दिया जाए।

आर्थिक संसाधन कम अतः अनुकूलतम प्रयोग जरूरी अतः पर्याप्त, समय पर विनियोग जरूरी।

विनियोग आवंटन की समस्याएं

- अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों में कितना विनियोग करें
- एक क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में कितना² विनियोग करें
- विभिन्न परियोजनाओं में कौन² सी तकनीक उपयोग हो
- क्षेत्र और परियोजनाओं की प्राथमिकता क्या हो
- विनियोग आवंटन कितनी अवधि तक करें

ये सभी चुनाव योजना उद्देश्यों पर निर्भर हैं।

निवेश की कसौटियाँ (CRITERIA OF INVESTMENT)

अर्थव्यवस्था की स्थिति, क्षेत्रवार प्राथमिकता, योजना उद्देश्यों के आधार पर इसका निर्णय करते हैं। इनके प्रकार हैं:-

विनियोग की कसौटियाँ:
- पूंजी आवर्त कसौटी - पोलक एवं बुकेनन
- सामाजिक सीमांत उत्पादकता कसौटी (A.E. Kahn, Chenary)
- पुनर्निवेश कसौटी (गेलेन्सन, लीबन्स्टीन)
- सेन की काल श्रेणी कसौटी (अमर्त्य सेन)

(1) पूँजी आवर्त कसौटी -
अन्य नाम आवर्त की दर की कसौटी उत्पादन से पूँजी अनुपात की कसौटी
इस कसौटी के अनुसार " UDC में पूँजी दुर्लभ , अतः ऐसी तकनीक का चुनाव करें जो पूँजी की 1 इकाई से अधिकतम उत्पादन प्रदान करें ।"
अथवा
उत्पादन अधिकतम करना हो तो विनियोग परियोजना चुनें जिनसे (की) पूँजी आवर्त दर ऊँची हो ।

इस कसौटी का लाभ :- UDC में साधन अनुकूल अधिकतम लाभ देती है।

सीमाएं :- (1) समय तत्व Time Lag की उपेक्षा करती है ।
(2) यह कसौटी परियोजनाओं के पूरक लाभ की उपेक्षा करती है । यदि COR↑ तो भी पूरक लाभ ↑ होने पर उन्हें प्राथमिकता जरूरी है ।
(3) आवर्त दर जितनी ↑ होगी पूँजी का मूल्य ह्रास ↑ अतः आवर्त की शुद्ध दर कसौटी ज्यादा उपयुक्त मापदण्ड होगा ।
(4) यह कसौटी केवल अल्पकाल में सही है ।
(5) जरूरी नहीं की रोजगार ↑ तो उत्पादन भी ↑ । क्योंकि श्रम गहनता पूँजी बचत तकनीकि निवेश आदि से भी श्रम की उत्पादकता कम रखी जा सकती है ।

निष्कर्ष :- यद्यपि यह कसौटी उपयुक्त है परन्तु UDC में बड़ी श्रमशक्ति एवं पूँजी दुर्लभता देखते हुए अधिक COR परियोजनाएं भी शुरू की जानी चाहिए ।

(2) सामाजिक सीमांत उत्पादकता कसौटी (SMP) –
SMP कसौटी A.E. काहन ने 1951 में चेनरी ने 1953 में इसे विकसित किया । यह सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पर आधारित ।
कसौटी के अनुसार " जब परियोजना में अन्य साधनों के साथ और

अधिक पूंजी लगाई जाए तो एक समय के बाद उसका सीमांत उत्पादन तब तक गिरेगा जब तक विभिन्न प्रयोगों में पूंजी की सीमांत उत्पादकता = नहीं हो जाए। अथवा
काहन के अनुसार, निवेश साधनों का प्रयोग सर्वाधिक उत्पादक परियोजना में होना चाहिए।

इस कसौटी का विस्तार प्रो० चेनरी ने S.M.P कसौटी के एक सूत्र का निर्माण कर किया:-

चेनरी के अनुसार
यदि देश का भुगतान शेष BOP = संतुलन हो तो,

$$SMP = \frac{X+E-L-M-O}{K}$$

यहाँ पर, X = बाजार में उत्पादन का बढ़ा हुआ मूल्य
E = शुद्ध मितव्ययताओं के कारण उत्पादन का जोड़ा हुआ मूल्य
L = श्रम लागत, M = माल लागत
O = उपरी overhead लागत (मूल्य ह्रास शामिल)
K = विनियोग की गई पूंजी

क्योंकि UDC में विदेशी पूंजी का मूल्य ↑↑ अतः
विदेशी पूंजी - देशी पूंजी का अंतर अधिक होता है। चेनरी इसे (r) कहते हैं।
यदि r_0 तो BOP संतुलित
यदि r_+ तो BOP घाटे में r_- तो BOP अतिरेक होगा।
अतः परिष्कृत सूत्र होगा

$$SMP = \frac{V-C}{K} + \frac{r(\alpha B_1 + B_2)}{K}$$

यहाँ V = सामा० मूल्य, C = साधन लागत, αB_1 = प्रारंभिक रचना सेवा पर BOP का प्रभाव, B_2 = परियोजना प्रचालन का BOP पर वार्षिक प्रभाव।

$P_{(-)}$ = आयात , $P_{(+)}$ = निर्यात

सरलता हेतु $r(\alpha B_1 + B_2) = P_r$ लिखें तो

$$SMP = \frac{v-c}{k} + \frac{P_r}{k}$$ (अंतिम सूत्र)

सीमाएँ -

① यह कल्पना सही नहीं है कि पूँजी की M.P. हमेशा = होती है।

② SMP कसौटी केवल वर्तमान के प्रभाव को बताती है। तथा स्वयं भी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से प्रभावित होती है।

③ इस कसौटी में अस्पष्टता एवं अनिश्चितता है। क्योंकि लाभों और लागतों का सही निर्धारण कठिन है।

④ अल्प रोजगार, बेरोजगारी जैसे साधनों का बाजार मूल्य अज्ञात है अतः सामा॰ मूल्य की गणना भी कठिन है।

⑤ SMP कसौटी का बड़ा दोष है कि यह विनियोग का N.I. पर एक बार पड़ने वाले प्रभाव तक सीमित है। भावी आय पर विनियोग के गुणक प्रभाव की उपेक्षा करती है।

③ पुनर्निवेश कसौटी

गेलेन्सन (1955) और लीबिन्स्टीन 1955 ने इस कसौटी का प्रयोग किया।

अन्य नाम (i) अतिरेक की दर का सिद्धान्त

(ii). सीमांत प्रति व्यक्ति निवेश गुणांक

गेलेन्सन एवं लीबिन्स्टीन वर्तमान के बदले भविष्य में प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने पर बल देते हैं। इस हेतु बचत दर ↑ जरूरी है। इससे आय पुनर्निवेश विनियोग होगा।

राष्ट्रीय आय (NI) = मजदूरी (W) + लाभ (P)

↙ उपभोग पर खर्च ↘ विनियोग

अतः लाभ ↑ तो विनियोग ↑ और प्रति व्यक्ति पूँजी उपलब्धता भी ↑
इसके लिए U.D. देशों में क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न आवश्यक है।
(C.M.E.)

इससे बचत ↑, पुनर्विनियोग अतिरेक भी ↑,
[निवेश अतिरेक की दर] का सूत्र इन्होंने निम्नानुसार बताया
निवेश अतिरेक (r) की दर निम्नानुसार बताई

$$r = \frac{p - e.w}{c}$$

r = निवेश अतिरेक की दर
p = प्रति मशीन उत्पादन
e = प्रति मशीन मनुष्यों की संख्या
w = वास्तविक मजदूरी दर
c = मशीन की लागत है

अतः विनियोग अतिरेक बढ़ाने के लिए पूँजी उत्पाद ↑ के लिए पूंजी/श्रम उत्पाद बढ़ाने हेतु पूंजी गहन तकनीकों का प्रयोग जरूरी है।

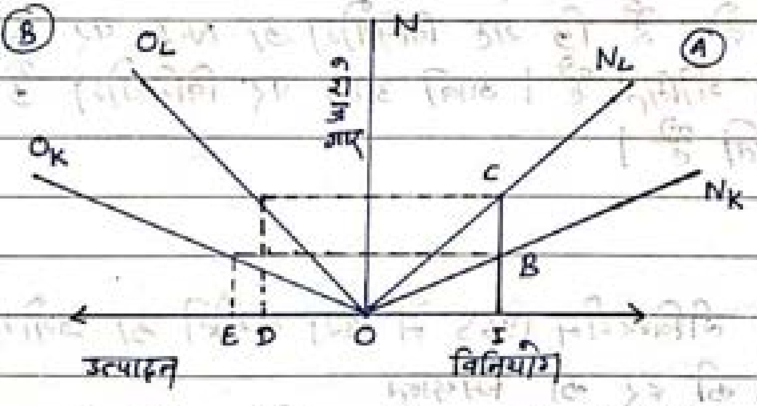

इस चित्र में A और B दो भाग हैं। (A) भाग पर विनियोग का रोजगार पर प्रभाव बताया गया है। (B) भाग में उत्पादन का रोजगार पर प्रभाव दर्शित है।

(1) रोजगार में विनियोग के प्रभाव की प्रक्रिया किरण NK द्वारा दर्शाए हैं। इस समय पूँजी गहन तकनीक उपयोग में लाई गई है।

(2) रोजगार में विनियोग के प्रभाव की प्रक्रिया किरण NL द्वारा बताया है इस समय श्रम गहन तकनीक उपयोग में लाई गई है।

(8) आग में उत्पादन का रोजगार पर प्रभाव (संबंध) दर्शाए हैं।
OK = पूँजीगहन तकनीक में उत्पादन, OL = श्रम गहन तकनीक में उत्पादन दर्शाया गया है।

पूँजी प्रधान तकनीक से JB रोजगार] पैदा हुए
श्रम प्रधान तकनीक से JC रोजगार]

पर श्रम प्रधान तकनीक से केवल OD उत्पादन हुआ
∵ पूँजी प्रधान तकनीक से OE उत्पादन (अधिक) हुआ
अतः उत्पादन बढ़ाने पूँजी प्रधान तकनीक प्रयोग में लानी चाहिए।
क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन दर अधिक होने से यह तकनीक रोजगार को भी बढ़ाएगी।

आलोचनाएं (CRITISISM)

(1) पुनर्निवेश गुणांक की मान्यता है कि समयोपरि उपभोग स्थिर है। पर यह धारणा अमान्य है।
(2) अमर्त्य सेन के अनुसार मजदूरी (W) लाभ (P) की धारा में पुनर्विनियोग के कारण रिसाव हो सकते हैं।
(3) कसौटी में पूँजी के मूल्य ह्रास पर विचार नहीं किया गया है।
(4) यह कसौटी पूँजी के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के विपरीत है। पूँजी k को बढ़ाते जावें तो एक समय बाद उसकी MP गिरेगी और प्रति व्यक्ति उत्पाद एवं पुनर्निवेश गुणांक (r) भी कम हो जाएंगे।
(5) अल्प विकसित देशों में पूँजीगहन उद्योगों में विनियोग में व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं।
(6) यह कसौटी एकांगी है। BOP का विनियोग पर प्रभाव की उपेक्षा करती है।
(7) एकस्टीन Ekestein के मतानुसार यह कसौटी आय के असमान वितरण को बढ़ाती है। फिर भी यह एक उपयोगी कसौटी है।

④ सेन की काल श्रेणी कसौटी

प्रो० अमर्त्य सेन ने 1967 में विनियोग की काल श्रेणी कसौटी दी है। उसे "समय की निश्चित अवधि में उत्पादन को अधिकतम बनाने की कसौटी की संज्ञा दी।"

उन्होंने इसकी व्याख्या एक उदाहरण से दी

माना कि, COR और बचत की दर ज्ञात हो तो दो तकनीकें (श्रम प्रधान एवं पूँजीगहन) का काल मार्ग Time path खींचा जाए तो ज्ञात होगा की दोनों तकनीकों में किससे अधिक प्रतिफल (Return) प्राप्त होगा। यह तालिका से स्पष्ट होगा।

अवधि	Project 1 (पूँजीगहन) H प्रतिफल '000	Project 2 श्रम गहन L प्रतिफल '000
1	4.0	6.0
2	5.0	7.0
3	6.0	8.0
4	7.5	9.0
5	9.0	10.0
6	10.5	11.0
7	12.0	11.5
8	13.5	12.0
9	15.0	12.5
10	17.5	13.0
	100.0	100.0

(a) = वर्ष 7–10 (H), (b) = वर्ष 1–6 (L)

(a) = L की अपेक्षा अतिरिक्त 58.0 − 49.0 = 9.0

(b) = H की अपेक्षा अतिरिक्त 51.0 − 42.0 = 9.0

यहाँ पर दो Project है H = पूँजीगहन L = श्रम गहन, समय अवधि 10 वर्ष है। अंत में दोनों से प्रतिफल 100 ('000) है।

प्रथम 6 वर्षों में L के प्रतिफल (42 मि०) है। शेष 4 वर्षों में

परियोजना H के प्रतिफल L से बढ़ जाते हैं।

Project (H) में प्रतिफल 42 से 58 मि० हो जाते हैं।

Project (H) में प्रतिफल कम हो कर 51 मि० से 49 मि० हो जाते हैं क्योंकि परियोजना से कुल प्रतिफल (100) में समान हैं। अतः उदासीन की स्थिति है।

अतः श्रमगहन तकनीक की तुलना में पूँजीगहन तकनीक उत्पादन न्यूनता को दूर करने में जो समय लेती है। उसे <u>पुनः प्राप्ति की अवधि</u> कहा जाता है। इसे अमर्त्य सेन ने चित्र से स्पष्ट किया है:-

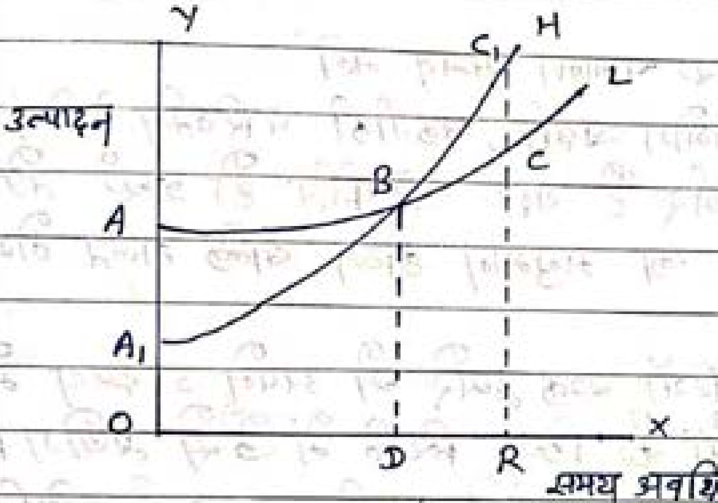

OX = समय अवधि
OY = उत्पादन
H एवं L वक्र दोनों तकनीकों से समय अवधि में उत्पादन के प्रवाह को प्रकट कर रहे हैं।

H तकनीक में शुद्ध में L की तुलना में कम उत्पादन (B के पूर्व) परन्तु वृद्धि की दर अधिक ऊँची है।

समय की D अर्थ अवधि में,
H तकनीक से L तकनीक में अधिक उत्पादन है परन्तु समय की R अवधि में यह H तकनीक L तकनीक से अधिक उत्पादन देती है।

अतः OR अवधि पुनः प्राप्ति की अवधि है।

पुनः प्राप्ति अवधि के आधार पर तकनीक का चुनाव निम्नानुसार होना चाहिए।

(i) जब R > C तो तकनीक L को चुनें
(ii) जब R < C तो तकनीक H को चुनें
(iii) जब R = C तो किसी भी तकनीक को चुनें।

अल्पविकसित (UDC) देशों हेतु यह कसौटी अधिक उपयुक्त है।

सीमाएँ

(1) यह एक समय अवधि (10 वर्ष) मानना काल्पनिक एवं मनमाना निर्णय है।

(2) काल श्रेणी को हमेशा के लिए चलाना संभव नहीं

(3) शेष साधन (मजदूरी दर, उपभोग प्रवृत्ति, तकनीकी परिवर्तन) जिन पर काल श्रेणी का विश्लेषण निर्भर है यदि परिवर्तित हो जाएं तो भावी विनियोग एवं उत्पादन का अनुमान कठिन बल्कि गलत होगा।

निष्कर्ष :- ये सभी कसौटियाँ एक दूसरे से अपने उद्देश्य में भिन्न नहीं हैं अतः किन कसौटियों को किस स्थिति में उसे प्रयोग किया जाए इसे जनसंख्या वृद्धि, रुचि, तकनीकी प्रगति, बाजार की स्थितियाँ, कीमत परिवर्तन, आय का वितरण एवं भुगतान शेष के साथ, आर्थिक सामाजिक दशाओं पर प्रभावों के आधार पर चयन किया जाना चाहिए।

तकनीक का चुनाव

The Choice of Techniques.

तकनीक का अर्थ

1.) तकनीक का अर्थ उत्पादन के ढंग या तरीके से है। उत्पादन कैसे किया जाये या उत्पादन कार्य हेतु विभिन्न साधनों (श्रम एवं पूंजी) को किस अनुपात में मिलाया जाये तकनीक इसकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति है।

2) उत्पादन एवं उत्पादन के साधनों के बीच पाये जाने वाले संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं।

3) जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है इस प्रक्रिया को उत्पादन तकनीक कहते हैं।

4) वस्तुओं और सेवाओं के लिए हुए उत्पादन स्तर को पहले कि तुलना में अपेक्षाकृत कम साधनों की सहायता से उत्पन्न करना तकनीकी प्रगति कहलाता है।

तकनीकी चुनाव की आवश्यकता एवं महत्व

1) विकास प्रक्रिया हेतु उपयुक्त तकनीक का चयन महत्वपूर्ण है। विकसित देश आधुनिक एवं नवीन तकनीक के कारण तीव्रगति से विकास किये हैं, वहीं अर्द्धविकसित देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण तकनीक पिछड़ापन है।

2) अर्द्धविकसित देशों की मुख्य समस्या अपने उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है। इसके लिए ऐसी तकनीक का चयन किया जाना चाहिए जो देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों के प्रयोग से अधिकतम उत्पादन प्रदान कर सके।

3) एक प्रभावशाली तकनीक वह है जो लागत को न्यूनतम करे एवं राष्ट्रीय उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करें।

तकनीक के प्रकार

तकनीक के दो प्रकार हैं –

(1) श्रम प्रधान तकनीक

(2) पूंजी प्रधान तकनीक

श्रम प्रधान तकनीक

(1) श्रम प्रधान तकनीक में उत्पादन हेतु श्रम की अधिक एवं पूंजी की कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है या रेड्डी के अनुसार "यह उत्पादन की वह तकनीक है जिसमें श्रम की अधिक मात्रा को पूंजी की कम मात्रा के साथ मिलाया जाता है।"

(2) इस तकनीक को श्रम गहन या पूंजी बचाव तकनीक भी कहते हैं।

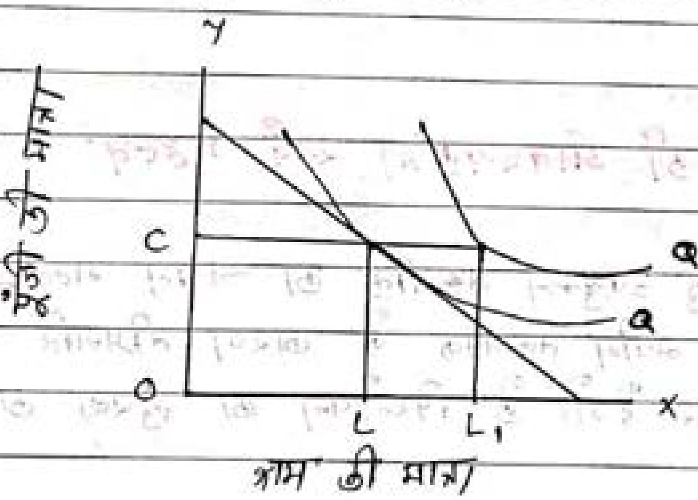

(3) OX = अक्ष पर श्रम की मात्रा
OY = — " — पूंजी की मात्रा

4) प्रारंभ में श्रम की OL मात्रा तथा पूंजी की OC मात्रा के प्रयोग से Q

उत्पादन करते हैं।

5) नई तकनीक का प्रयोग करने पर उतनी ही पूँजी OC तथा श्रम की मात्रा बढ़ाकर OL₁ करने पर उत्पादन का ऊंचा स्तर प्राप्त होता है।

6) इस तकनीक में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए श्रम की अधिक मात्रा का उपयोग किया है अतः यह श्रम प्रधान तकनीक कहलाती है।

पूंजी प्रधान तकनीक

(1) पूँजी प्रधान तकनीक में उत्पादन हेतु पूँजी की अधिक मात्रा एवं श्रम की कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है।

(2) भिन्ट के अनुसार " उत्पादन की दृष्टि से पूंजी प्रधान तरीके आधुनिक तरीके या यांत्रिक तरीकों को बताते हैं। "

(3) इस तकनीक को पूँजी गहन या श्रम बचाव तकनीक भी कहते हैं।

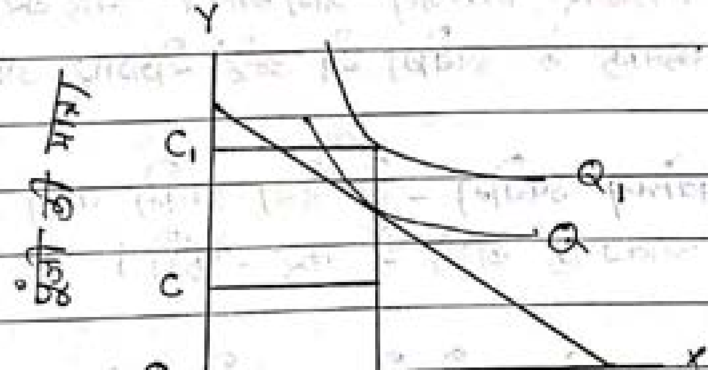

(4) रेखाचित्र में प्रारंभ में श्रम की OL मात्रा तथा पूँजी की OC मात्रा के प्रयोग से Q उत्पादन प्राप्त करते हैं।

(5) नई तकनीक का प्रयोग करने पर श्रम की उतनी ही मात्रा OL तथा पूँजी की मात्रा बढ़ाकर OC, करने पर उत्पादन का ऊँचा स्तर प्राप्त होता है।

(6) इस तकनीक में उत्पादन की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए पूँजी की अधिक मात्रा का प्रयोग किया गया है अतः यह पूँजी प्रधान तकनीक कहलाती है।

अर्द्धविकसित देशों में तकनीक

अर्द्धविकसित राष्ट्रों में श्रम प्रधान या पूँजी प्रधान किस तकनीक का चयन किया जावे इसके पक्ष में तर्क -

श्रम प्रधान तकनीक के पक्ष में तर्क

(1) प्रो० नर्क्से, लुईस, पॅाल रोजन, किंडल बर्जर, मेयर बाल्डविन आदि ने इस तकनीक का समर्थन किया।

(2) रोजगार का विस्तार - अर्द्धविकसित देशों में बड़ी मात्रा में अदृश्य बेरोजगारी, अल्प रोजगार, निष्क्रिय श्रम शक्ति, अर्द्ध बेरोजगारी पायी जाती है। श्रम गहन तकनीक के उपयोग से उन्हें रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं।

(3) दुर्लभ पूँजी का सर्वोत्तम उपयोग - ये देश अपने पास उपलब्ध दुर्लभ पूँजी का प्रयोग अन्य आवश्यक कार्यों में कर सकेंगे।

(4) उत्पादन की सस्ती तकनीक - ये देश अपने यहां उपलब्ध सस्ते श्रम का उपयोग करके अपनी उत्पादन लागत कम कर सकते हैं।

(5) आंतरिक साधनों का प्रयोग - श्रम प्रधान तकनीक देश के आंतरिक साधनों पर निर्भर होती है जबकि पूंजी प्रधान तकनीक में विदेशी सहायता व तकनीकी ज्ञान जरूरी होता है।

(6) मुद्रा प्रसार पर रोक - श्रम प्रधान तकनीक अपनाने से उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति शीघ्र एवं बड़े पैमाने पर हो जाती है जिससे मुद्रा प्रसार पर रोक लगती है।

(7) विदेशी विनिमय की बचत - श्रम प्रधान तकनीक में प्रयुक्त औजार एवं उपकरण देश में ही उत्पादित किये जा सकते हैं, इन्हें विदेशों से आयात नहीं करना पड़ता, जिससे विदेशी विनिमय बचता है।

(8) विकेन्द्रित समाज की स्थापना - इस तकनीक का उपयोग छोटे, लघु, कुटीर उद्योगों में होता है जिससे विकेन्द्रित समाज की स्थापना हो जाती है।

(9) उपभोग का उच्च स्तर - यह तकनीक मजदूरी के स्तर को ऊंचा उठाती है, जिससे उपभोग व्यय बढ़ता है तथा उपभोग स्तर ऊंचा हो जाता है।

(10) मितव्ययिता - इस तकनीक को अपनाने से आर्थिक सामाजिक लागत कम हो जाती है।

(11) आर्थिक समानता - इस तकनीक को अपनाने से रोजगार बढ़ता है जिससे राष्ट्रीय आय का वितरण समान हो जाता है।

(12) औद्योगीकरण के दोषों से छुटकारा - लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर आधारित होने से औद्योगीकरण के दोषों से छुटकारा मिलता है।

(13) प्रशासकीय साधनों की कम आवश्यकता - छोटे पैमाने पर उत्पादन होने के कारण विशेष प्रशासकीय साधनों की आवश्यकता नहीं होती।

(14) शहरी ग्रामीण संतुलन - इस तकनीक से ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन

मिलता है जिससे गाँव, कस्बों - शहर में संतुलन कायम रखने में मदद मिलती है।

पूंजी प्रधान तकनीक के पक्ष में तर्क

(1) हार्वे लीबिन्स्टीन, पाल बरान, हर्षमैन, मोरिस डाब ने उसका समर्थन किया।

(2) तीव्र आर्थिक विकास - पूंजी प्रधान तकनीक आय वृद्धि एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।

(3) जीवन स्तर में वृद्धि - इस तकनीक से बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण उत्पादन लागत कम हो जाती है जिससे उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक वस्तुएं मिलने से उनका जीवन स्तर उच्च हो जाता है।

(4) उत्पादकता में वृद्धि - पूंजी प्रधान तकनीक अपनाने से प्रति श्रमिक उत्पादकता बढ़ती है एवं अधिक उत्पादन संभव होता है।

(5) श्रम शक्ति का उचित उपयोग - अर्द्धविकसित देशों में श्रम का आधिक्य अस्थायी स्थिति है अतः जरूरी है प्रारंभ से ही श्रम बचाव तकनीक का उपयोग किया जाये ताकि बाद में उसकी दुर्लभता से बचा जा सके।

(6) रोजगार में वृद्धि - पूंजी प्रधान तकनीक अपनाने से विकास दर तेजी से बढ़ती है, जिससे दीर्घकाल में श्रमशक्ति को अधिक रोजगार अवसर मिलते हैं।

(7) अधः संरचना का विकास - देश के तीव्र आर्थिक विकास हेतु सामाजिक आर्थिक ऊपरि पूंजी का विकास जरूरी है। ये कार्यक्रम प्रायः पूंजी गहन होते हैं।

(8) मितव्ययितायें - इस तकनीक में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से बचतें

प्राप्त होती है, जिससे लागत कम होती है एवं उत्पादन बढ़ता है।

(9) तकनीकी प्रगति के लाभ - इस तकनीक में उत्पादन इकाइयां नवीन आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर कुशलता से उत्पादन करती हैं।

(10) विकासमय वातावरण - जनसंख्या वृद्धि की ऊँची दर के कारण इन देशों में पूंजी निर्माण की दर कम होती है। पूंजी निर्माण एवं विकासमय वातारण हेतु पूंजी प्रधान तकनीक जरूरी है।

(11) विकास प्रक्रिया पर अधिक धावक प्रभाव - पूंजी प्रधान परियोजनाओं का प्रभाव श्रम प्रधान परियोजना से ज्यादा होता है।

(12) कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक - इस तकनीक से अर्थव्यवस्था में कार्य कुशलता बढ़ती है। प्रशिक्षण एवं प्रबंधन में यह तकनीक सहायक है।

(13) प्रदर्शन प्रभाव - अर्द्धविकसित देशों में आय बढ़ते ही नई आवश्यकताओं का सृजन होता है। इसकी पूर्ति हेतु प्राथमिक उद्योग जो आधारभूत एवं पूंजीप्रधान होते हैं का विकास जरूरी हो जाता है।

पूंजी प्रधान तकनीक की सीमायें

1. अर्द्धविकसित देशों में उपलब्ध संसाधनों के प्रतिकूल है।
2. इस तकनीक से अल्प विकसित देशों के संसाधनों का अपव्यय होता है।
3. मशीनों व तकनीकों के आयात से भुगतान शेष प्रतिकूल होता है।
4. मशीनों तथा उपकरणों का अनुरक्षण एवं उपयोग कठिन कार्य है।
5. इन देशों में इस तकनीक लायक आवश्यक सहायक सेवायें उपलब्ध नहीं होती।

तकनीक के चुनाव को निर्धारित करने वाले घटक

(1) आर्थिक सामाजिक उद्देश्य
(2) संस्थागत व्यवस्था एवं घटक
(3) साधनों की उपलब्धता
(4) पूर्व एवं वर्तमान तकनीक का स्तर
(5) समय की अवधि

अर्द्धविकसित देशों में तकनीक के उपयोग में कठिनाइयाँ

(1) अशिक्षित जनसंख्या
(2) देशों में वित्तीय साधनों का अभाव
(3) योग्य साहसियों की सीमित संख्या
(4) पोषण शक्ति कम, योग्य प्रशासक एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव
(5) परम्परागत सामाजिक रूपरेखा
(6) उपलब्ध तकनीक व ज्ञान इन देशों के अनुकूल बनाने की कठिनाई
(7) वातावरण एवं आवश्यकतायें विकसित देशों से भिन्न
(8) आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन की समस्या
(9) श्रम बचाव तकनीकें यहां उपयुक्त नहीं

तकनीकी चयन में सामंजस्य उपयुक्त तकनीक

(a) बकील एवं ब्रह्मानंद के अनुसार - अल्पविकसित देशों को ऐसी तकनीक का चयन करना चाहिये

(1) जिसको सीखने में समय कम लगता हो।
(2) जिसमें प्रारंभिक निवेश एवं उत्पादन प्रारंभ होने में समयांतर कम हो।
(3) प्रारंभिक निवेश में कम पूंजी की आवश्यकता हो।
(4) विशिष्ट एवं कुशल श्रमिकों के रूप में निवेश की कम मात्रा लगे।

(5) कच्चे माल तथा दुर्लभ साधनों की बचत हो।
(6) उत्पादन स्तर एवं उत्पादकता में वृद्धि हो।
(7) उत्पत्ति के साधनों के स्टाक में वृद्धि हो।

(b) शूमेकर के अनुसार -
अर्द्धविकसित एवं विकासशील देशों के लिए जरूरी है कि वे उन्नत देशों के तकनीकी ज्ञान के भंडार से लाभ उठायें और अपनी सामाजिक आर्थिक एवं तकनीकी क्षमताओं के अनुरूप उन्नत देशों की तकनीक में परिवर्तन कर उन्हें अपनायें। प्रो. शूमेकर ने इस तकनीक को मध्यवर्ती तकनीक कहा।

(c) इस प्रकार श्रम प्रधान तकनीक जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर देश में उपलब्ध श्रमशक्ति को काम पर लगाती है वहीं पूंजी प्रधान तकनीक देश के औद्योगिक विकास को ऊंचा उठाकर विकास की गति को तीव्र करती है।

निष्कर्ष :-
अर्द्धविकसित देशों को मध्य मार्ग अपनाते हुए भारी तथा आधारभूत उद्योगों की स्थापना एवं अधः संरचना के निर्माण में पूँजी प्रधान तकनीक तथा कृषि एवं उपभोग वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिये।

योजना आयोग - 15 मार्च 1950 गठन
- प्रधानमंत्री अध्यक्ष

NDC राष्ट्रीय विकास परिषद - 6 अगस्त 1952

① प्रथम पंचवर्षीय योजना → 1 अप्रैल 1951 31 मार्च 1956
- हैरॉड डोमर मॉडल
प्राथमिकता - कृषि विकास
विकास दर - लक्ष्य 2.1% प्राप्ति 3.6%
work - भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई।

② द्वितीय पंचवर्षीय योजना - 1956 - 1961
- P.C महालनोबिस
प्राथमिकता - औद्योगिक विकास
विकास दर - लक्ष्य 4.5% प्राप्ति - 4.2%
work - राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना।
- "भारत सहायता क्लब" की स्थापना।

③ तृतीय पंचवर्षीय योजना :- 1961 - 1966
प्राथमिकता - आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया।
विकास दर - लक्ष्य 5.6%, प्राप्ति 2.8%
work - हरित क्रांति शुरुआत
1966 - 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजना चलाई गई।
~~योजना अवकाश~~

(4) चौथी पंचवर्षीय योजना - 1969 - 1973

प्राथमिकता - स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया।
- कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया।

* इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष D R गाडगिल ने तैयार किया।

विकास दर - लक्ष्य - 5.7% प्राप्ति - 3.4%

Work - 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और ISRO की स्थापना।

* इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही।

(5) पाँचवी पंचवर्षीय योजना - 1974 - 1978

प्राथमिकता - • गरीबी उन्मूलन (निवारण)
• आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया।
• गरीबी हटाओ का नारा

• इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया।

विकास दर :- लक्ष्य 4.4%, प्राप्ति 4.8%

[मिर्डल ने पिछड़े देशों के लिए का प्लान दिया था - रोलिंग प्लान इसे 1978 ई. वाली मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने इसे स्वीकारा था।]

Work - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
• 1975 में एक योजना TPP (Twenty Point Program)
• गरीबी हटाओ अभियान लाया गया।

✓ योजना अवकाश :- 1979 - 80

(6) छठी पंचवर्षीय योजना :- 1980 - 1985
प्राथमिकता - गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था।
विकास दर - लक्ष्य 5.2%, प्राप्ति 5.7% ✓
Work - ग्रामीण बेरोजगार, गरीबी निवारण से सम्बन्धित कई योजना चालू की गई
- TRYSEM, IRDP, NREP।

(7) सातवीं पंचवर्षीय योजना - 1985 - 1990
मॉडल - जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल
प्राथमिकता - रोजगार, शिक्षा और जनस्वास्थ्य पर बल दिया गया
'भोजन, काम और उत्पादन' का नारा इसी योजना
विकास दर - लक्ष्य 5%, प्राप्ति - 6% ✓
Work - गरीबी की माप हुई (लकड़वाला समिति ने)
- जवाहर रोजगार योजना। ✓

✓ [1990 - 91, 91 - 92 वार्षिक योजना चलाई गई।]

(8) 8 वीं पंचवर्षीय योजना - 1992 - 1997।
प्राथमिकता - रोजगार वृद्धि, आधुनिकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था।
विकास दर - लक्ष्य 5.6%, प्राप्ति 6.8% ✓
Work - प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई।
- LPG (System)

(9) 9 वीं पंचवर्षीय योजना - 1997 - 2002

प्राथमिकता - मानव विकास के साथ-साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया।

विकास दर - लक्ष्य 6.5%, प्राप्ति 5.5%

* यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही।

(10) 10वीं पंचवर्षीय योजना - 2002 - 2007

प्राथमिकता - गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना।

- अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना।

विकास दर - लक्ष्य 8%, प्राप्ति 7.7%

(11) 11 वीं पंचवर्षीय योजना - 2007 - 2012

प्राथमिकता - तीव्रतम एवं समावेशी विकास।

विकास दर - लक्ष्य 9%, प्राप्ति 7.9%

Work - आम आदमी बीमा योजना

- राजीव आवास योजना

- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

(12) 12वीं पंचवर्षीय योजना :- 2012 - 2017
प्राथमिकता - तीव्रतम एवं समावेशी विकास
* 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया, और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की।

(1) भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी?
- राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा (NDC)

(2) योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई जा चुकी हैं?
- 12

(3) भारत में 'योजनावकाश' था -
- 1966 के सूखे के पश्चात

(4) प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी?
- कृषि क्षेत्र

(5) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था?
- P. C. महालनोबिस

(6) किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में तीन लौह-इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे?
- द्वितीय

(7) तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था?
- कृषि

⑧ 'भारत सहायता क्लब' की स्थापना किस पँचवर्षीय योजनावधि के दौरान की गई थी?
- द्वितीय

⑨ किस पँचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया।
- तृतीय

⑩ भारत में 'गरीबी हटाओ' का नारा किस पँचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था?
- पाँचवीं

⑪ नि. में से कौन-सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है?
① प्रथम - 1951-56 ③ तृतीय - 1961-66
② द्वितीय - 1956-61 ✓④ चतुर्थ - 1966-71 1969-1973

⑫ दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी?
- भारी उद्योग

⑬ किस पँचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही?
- चौथी

⑭ नि. योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही?
- 11वीं (7.9%)

⑮ राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था?
- 1952 (NDC)

(16) भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
1950

(17) किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी?
5 वीं

(18) राष्ट्रीय नियोजन में "रोलिंग प्लान" (5th) की अवधारणा लागू की गयी थी?
जनता सरकार के द्वारा

(19) 11 वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था?
समावेशी आर्थिक वृद्धि

(20) किस पंचवर्षीय योजना में "भारी उद्योग" को प्राथमिकता दी गई थी?
दूसरी

(21) नि. में से कौन सा 12 वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है?
1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017

(22) भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी?
हैरॉड डोमर मॉडल

(23) कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल चार वर्ष की थी?
पाँचवी

(23) महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है?
दूसरी

(२१) देश में कौन से तीन तिथियों को [illegible] के रूप में मनाया जाता है ?

- १९८८-८९

स्थानांतरण और बेरोजगारी का हैरिस-टोडैरो मॉडल
(The Harris-Todaro Model of Migration and Unemployment)

Migration Unemployment and Development
"A Two sector Analysis"
John R. Harris and Michael P. Todaro

द्वि क्षेत्रीय मॉडल
मार्च 1970
ग्रामीण - शहरी उत्प्रवासन

उद्देश्य :- मॉडल का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में शहरी बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करना था एवं यह मॉडल मुख्य रूप से इन विकासशील देशों में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति पर अध्ययन करना है।

मॉडल का आधारभूत योगदान श्रम बाजार के अनुकूल एवं उपयुक्त घटकों का प्रतिपादन करना था जिससे विकासशील देशों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण परंपरागत क्षेत्र में मजदूरी में वृद्धि हो सके।

टोडारो - विरोधाभास

TODARO - PARADOX

"शहरी बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य वाली नीतियां विपरीत प्रभाव डालती है: वे शहरी बेरोजगारी को कम करने के बजाय उसमें वृद्धि करेंगी।"

"विकासशील देशों में रोजगार सृजन प्रयासों के बावजूद बेरोजगारी

में वृद्धि होना।"

मॉडल की मान्यताएँ

(1) अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अथवा कृषि (A) और शहरी अथवा विनिर्माण (M) दो क्षेत्र हैं।

(2) ग्रामीण क्षेत्र कृषि पदार्थ की X_A इकाइयां और शहरी क्षेत्र निर्मित वस्तु की X_M इकाइयां उत्पादित करता है। प्रत्येक क्षेत्र केवल एक ही वस्तु का उत्पादन करता है।

(3) यह मॉडल अल्पकाल में चालू होता है।

(4) दोनों क्षेत्रों में पूँजी स्थिर मात्राओं में ($\bar{K}$) उपलब्ध होती है।

(5) दोनों क्षेत्रों में उत्पादकों के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है।

(6) शहरी मजदूरी W_M पर निश्चित है और ग्रामीण मजदूरी W_A पर और $W_M > W_A$

(7) अर्थव्यवस्था में N श्रमिक पाए जाते हैं जिनमें से N_A ग्रामीण क्षेत्र में और N_M शहरी क्षेत्र में रोजगार में लगे हैं।

(8) ग्राम्य-शहरी स्थानांतरण उतनी देर तक चलता रहता है, जब तक कि वास्तविक आय अधिक है।

(9) उत्प्रवास की लागत शून्य है।

(10) ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की श्रमिक का स्थानांतरण, शहरी ग्रामीण मजदूरी

अंतर का धनात्मक फलन है।

मान्यताएं

① अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की कुल संख्या L है, जिसमें LR ग्रामीण व LU शहरी क्षेत्र में कार्यरत है।

② शहरी मजदूरी दर W स्थिर है, एवं ग्रामीण मजदूरी दर (श्रमिक सीमांत उत्पादकता) WR है W>WR.

③ शहरी रोजगार की मात्रा स्थिर है,

④ कुल शहरी श्रम शक्ति L-LR

⑤ शहरी बेरोजगार (L-LR)-LU

⑥ आशातीत शहरी आय W

⑦ आशातीत शहरी आय W, शहरी मजदूरी दर एवं शहरी रोजगार दर W[LM\(L-LA)], का गुणन फल है जो श्रम प्रवासन को निर्धारित करती है -

W[LU\(L-LR)]

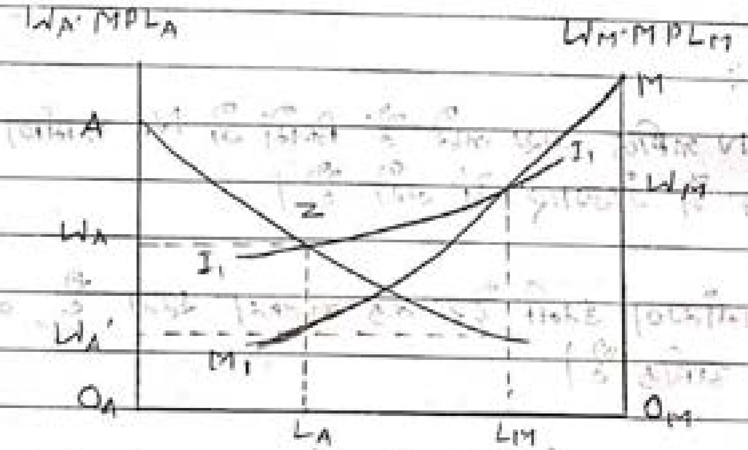

ग्रामीण शहरी प्रवासन दर

$m = f(EU/LU, W, z)$ — LU = शहरी श्रम शक्ति

m = ग्रामीण शहरी प्रवासन दर

$W = YU/YR$ — M = कुल ग्रामीण शहरी प्रवास

$m = M/LR$ — LR = ग्रामीण श्रम शक्ति

$EU/LU > 0$, — EU = शहरी रोजगार स्तर

$W > 1$, — YU - शहरी वास्तविक आय

$z \pm$ — YR - ग्रामीण वास्तविक आय

W - ग्रामीण शहरी वास्त. आय अनुपात

z - व्यक्तिगत घटक

ग्रामीण शहरी प्रवासन दर = वास्तविक शहरी रोजगार दर, ग्रामीण शहरी वास्तविक आय अनुपात एवं व्यक्तिगत घटक का फलन है।

सारांश

(1) सामान्यतया प्रवासन, लागत लाभ की धारणा से प्रभावित होता है -

लागत - वर्तमान ग्रामीण रोजगार आय

लाभ - शहरी आशातीत आय

(2) प्रवासन का निर्णय वास्तविक शहरी-ग्रामीण आय अंतर के स्थान पर आशातीत अंतर का परिणाम होता है।

(3) शहर में रोजगार प्राप्ति की संभावना, शहरी रोजगार स्तर से प्रत्यक्षत: सम्बंधित होती है।

(4) शहरों में ऊँची आय प्रत्याशा, अधिक प्रवासन को प्रेरित करती है, जिससे बेरोजगारी में और अधिक वृद्धि होती है।

नीतिगत निष्कर्ष

(1) शहरी-ग्रामीण रोजगार अवसरों में अंतर को कम करना आवश्यक है।
(2) शहरी बेरोजगारी दूर करने में केवल शहरी रोजगार सृजन प्रयास संतोषजनक नहीं होते।
(3) मजदूरी सब्सिडी द्वारा श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।
(4) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।
शहरी क्षेत्र में औद्योगिक मजदूरी सब्सिडी दी जाए।
छाया मजदूरी कसौटी का क्रियान्वयन कृषि उत्पादन व शहरी रोजगार सृजन के लिए प्रभावी होगा मजदूरी सब्सिडी के लिए लागत रहित एक मुक्त कर लगाया जाए।

FCI Food Corporation of India
(1964)

भारतीय खाद्य निगम - भारत का एक निगम है। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदामों में भण्डारित करता है।

IDBI

Unit- I

Economic Planning :-

आर्थिक आयोजन :- (Page-5-314)

प्रो. रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार " आर्थिक आयोजन उत्पादन तथा विनिमय की निजी क्रियाओं का सामूहिक नियन्त्रण या प्रतिस्थापन है।"

लुईस लॉर्डविन की परिभाषा के अनुसार :- "आर्थिक आयोजन आर्थिक संगठन की वह स्कीम है, जिसमें व्यक्तिगत तथा अलग प्लांट, उद्यम तथा उद्योग एक सकल व्यवस्था की समन्वित इकाइयाँ हैं, ताकि एक निश्चित समय के भीतर लोगों की जरूरतों की अधिकतम सन्तुष्टि के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाए।"

आर्थिक आयोजन का मतलब है, समय की निश्चित अवधि के भीतर निश्चित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अर्थव्यवस्था का आयोजित नियन्त्रण तथा निर्देशन ।

आयोजन के उद्देश्य

Objectives of Planning

1. पूर्ण रोजगार
2. असमानताओं को दूर करना
3. गरीबी को दूर करना
4. साधनों का उचित प्रयोग
5. सन्तुलित क्षेत्रीय विकास
6. त्वरित विकास
7. आत्मनिर्भरता
8. सामाजिक सुरक्षा
9. आर्थिक स्थिरता
10. राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना
11. अधिकतम सामाजिक कल्याण

Unit - I

अल्पविकसित देशों में आयोजन की आवश्यकता

(Need for Planning in Underdeveloped Countries)

1. पूँजी निर्माण के लिए
2. बेरोजगारी दूर करने के लिए
3. सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए
4. सामाजिक एवं आर्थिक उपरि सुविधाओं का विकास
5. वित्तीय संस्थाओं का विकास
6. दरिद्रता दूर करना
7. तकनीकी विकास के लिए
8. साधनों का उचित उपयोग
9. उत्पादन समस्याओं का समाधान
10. आर्थिक सुरक्षा

भारतीय योजनाओं की सफलता एवं असफलता की बताइए। (उत्तर)

भारतीय नियोजन की उपलब्धियाँ / सफलताएँ

Achievements of Indian Planning

भारत में आर्थिक नियोजन को 1 अप्रैल, 1951 से प्रारम्भ किया गया।

1. प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि
2. कृषि का विकास
3. औद्योगिक विकास
4. सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार
5. लघु और कुटीर उद्योगों का विकास
6. बचत व विनियोग दरों में वृद्धि
7. विदेशी व्यापार का विकास
8. आत्म निर्भरता

(9) परिवहन एवं संचार साधनों के क्षेत्र में प्रगति
(10) शिक्षा का प्रसार
(11) स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि
(12) बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति
(13) पर्यावरण सुरक्षा
(14) सामाजिक न्याय

भारतीय नियोजन की विफलताएँ

(Failures of Indian Planning)

(1) प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में धीमी प्रगति
(2) रोजगार
(3) आर्थिक विषमता में वृद्धि
(4) आर्थिक अस्थिरता
(5) कृषि क्षेत्र में असफलता
(6) औद्योगिक क्षेत्र में विषमता
(7) साधन संग्रह के क्षेत्र में विषमताएँ
(8) विदेशी सहायता पर निर्भर
(9) दोषपूर्ण नियन्त्रण नीति

2013 → भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य बताइये। (3M)
भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य व उद्देश्य (कर्ना - 144)
दो भाग
↓
(1) अल्पकालीन उद्देश्य
(2) दीर्घकालीन उद्देश्य